Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 03 30 मार्च, 2021 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से जननायक चौधरी देवी लाल बनाम किसान आन्दोलन

06 अप्रैल पुण्य तिथि पर विशेष

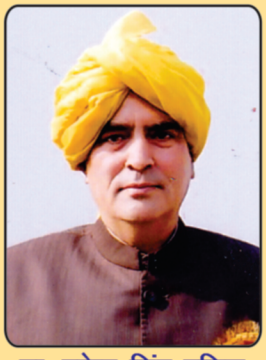

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

06 अप्रैल 2001, राष्ट्र के समस्त किसान–कामगार–काश्तकार के लिये एक अत्यधिक शोक दिवस के तौर से विख्यात रहेगा। इस दिन राष्ट्र के पूर्व उपप्रधान मंत्री जननायक ताऊ देवी लाल का पार्थिक शरीर उनके निवास स्थान 100 लोधी रोड़ नई दिल्ली में जनता जनार्धन के दर्शन हेतू जीवन की अंतिम यात्रा की इंतजार में रखा गया था। ताऊ की जीवन गाथा ग्रंथ का प्रारूप भी प्रागंण में आम आदमी की टिप्पणी हेतु उपलब्ध था। अतः एक लेखक ने ग्रंथ में बरवान किया कि "जन–जन की आवाज धरती पुत्र की आत्मा धरती में विलिन हो गई"। तत्पश्चात् भारतीय सेना का सैनिक दस्ता तिरंगे सहित वहां पहुंचा और पार्थिक शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में सुशोभित कर सेना बैड ने शोक की सम्मानित ध्वनि बजानी शुरू की व सशस्त्र सैनिक टुकड़ी ने पार्थिक शरीर को सलामी देकर फूलों से सुशोभित सैनिक वाहन में रखा व धीरे–धीरे वाहन अतिंम यात्रा स्थल की ओर रवाना हुआ। अंतिम यात्रा का कारवां बढ़ता रहा और राष्ट्र के कोने–कोने से लाखों की भीड़ कारवां के साथ उमड़ पड़ी और जननायक को अंतिम सलामी देते हुए आकाशभेदी नारे – "जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ देवी लाल तेरा नाम रहेगा" गुजने लगे। उनके श्रद्धाजंली समारोह में स्व० प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा था कि वे " जन नायक और सच्चे सिपाही थे जो जीवन प्रयंत दलित, काश्तकार व ग्रामीण वर्ग के लिये संघर्षरत रहे।"

आज किसान आंदोलन के प्रति सरकार की बेरूखी से व्यपित होकर ताऊ देवी लाल को याद कर लेखक अत्यन्त भावुक है क्योंकि ताऊ देवी लाल ने 1977 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ही किसान–काश्तकार के लिये हुकांर भरी व कहा था कि "किसान–काश्तकार का बेटा देश का प्रधानमंत्री व दलित का बेटा राष्ट्रपति बनेगा" तो तभी देश आर्थिक व प्रजातात्रात्मक दृष्टि से सम्पन्न होगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वालम्बी भारत का सपना साकार होगा। इसी प्रकार देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर हरियाणा व केन्द्र में शासक दलो के प्रति जनता का असन्तोष बढ़ने लगा व कुछेक आत्याधिक स्वार्थी व भ्रष्ट राजनेताओं के विरूध नारे लगने लगे व रोष उभरने लगा "धोखेबाज व भ्रष्ट राजनेता गदी छोडो, किसान विरोधी शासक गदी छोड़ों"। तब 1977 से 1979, 1987–88 व 1989 में ताऊ देवी लाल उन्हीं मुदों को लेकर जनता की आवाज बन आगे बढ़े व प्रजातंत्र की मजबूती के लिये नया नारा बुलन्द किया कि "लोकराज लोक लाज से चलता है" और जनहित के लिये स्वार्थी व भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का कानून बनाने की मांग की। लेकिन यह अत्यन्त दुख का विषय है कि आज साढ़े तीन मास से कृषि विरोधी तीन कानूनों को रद्द करने व किसानों की समसयाओं का हल करने के लिये सर्घषरत किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति केन्द्रीय सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। इस जन–आंदोलन में लगभग 300 किसान जान गवा चुके है और सरकार किसान–काश्तकार को दोफाड़ करने में लगी है। इसी प्रकार के किसान–काश्तकार व कृषि विरोधी आंदोलन सन् 1917, 1918 व 1928 में भी हो चुके है जिसमें सरकार को जन साधारण के भारी रोष का सामना करना पड़ा था और ये तीनों आंदोलन सफल रहे थे। वर्ष 1917 का जन आंदोलन शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह की अगुवाई में "पगंड़ी सम्भाल जटा" के जोशीले नारे में चलाया गया था। आज फिर किसान की पगड़ी उछाल दी गई है जिसकी लाज के लिये एकछत्र दंबग व निश्पक्ष किसान नेता की आवश्यकता है, अतः आज जनता चौ० देवीलाल जैसे किसान व जनप्रिय नेता की राह देख रही है जो जनता–जनार्धन की आवाज को उठाने के लिये जनता के बीच पहुंच कर रेल व सड़क यातायात तक अवरूध कर देते थे।

चौधरी देवीलाल ने भातीय राजनीति का हर पद ग्रहण किया लेकिन अपनी जमीनी सोच और कार्यशैली में कभी बदलाव नहीं लाए। वे हर गांव के दूर कोने में बसने वाले को नाम से जानते थे, उनकी काटड़ी–बछड़ी की बात करते थे। पद की गारिमा–प्रतिष्ठ को बरकरार रखते हुए वे दरिद्र नारायण के घर द्वार तक पहुंचे और उनके जीवन में विकास की किरण भी पहुंचाई। सत्ता के बिना भी उन्होने लोगों के दिलों पर राज किया। वे शरीर जरूर छोड़ गए लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवित है। यह ताऊ का करिश्माई व्यक्तित्व ही था कि विधान सभा की की 90 में से 85 सीटें जीते तथा 1999 में चौटाला जी के गठबंधन में भाजपा ने लोकसभा की सभी 10 सीटों पर विजय पताका फहराई।

उन्होने 14–15 वर्ष की आयु में ही संघर्ष का दामन थाम लिया था और वही उनकी जीवन शैली बन गया तभी उन्होने अपना नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। कांग्रेंस मुक्त भारत की वास्तविक नींव चौधरी देवी लाल ने ही रखी थी। संपूर्ण राष्ट्र को उन्होने एक सूत्र में पिरो दिया और पहली बार केंद्र में कांग्रेंस को सत्ता के गलियारों से दूर कर दिया। वे विपक्षी एकता के कर्णधार बने। वे किंग मेकर की भूमिका में ही रहे कभी किंग बनने का सपना ना देखा। प्रधानमंत्री ताज

शेष पेज–2 पर

शेष पेज–1

सर्वसम्मति से उन्हे दिया गया लेकिन तप–त्याग की मूर्ति चौधरी देवीलाल ने बहुत गारिमामय ढंग से श्री वी पी सिंह के सिर पर धर दिया। जब वे उनके मानकों पर खरे नहीं उतरे तो श्री चंद्रशेखर को गद्दी पर बिठा दिया और खुद संघर्ष की शैली पर चल निकले। ऐसा भी नहीं है कि केवल उनकी सोच खेत खलिहान तक ही सीमित रही हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। घुमंतू परिवारों के बच्चों को स्कूल लाने हेतू प्रलोभन एक रूपया प्रति दिन से शिक्षा का प्रसार, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, गरीब बच्चों को वर्दी, कापी–किताब के साथ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क जन स्वास्थ्य हेतू 'जच्चा–बच्चा कल्याण योजना, प्रशासन आपके द्वार, भ्रष्ट्राचार बंद पानी का प्रबंध, किसान के खेत तक पक्के खालें, सरकारी भूमि पर लगे वृक्षों से किसान की फसल को होने वाली क्षतिपूर्ति हेतू हिस्सा, वृद्धा सम्मान पैंशन, कन्यादान, विकलांग पैंशन, इटरव्यू के लिये जाने वाले छात्रों का किराया माफी आदि उनकी इतनी गहरी सोच को कोई कैसे नजर अंदाज कर सकता है। अतः पूरे राष्ट्र में ताऊ आज समाज कल्याण योजनाओं के सुत्राधार माने जाते हैं।

खेल खिलाडियों और सुरक्षा सेनाओं के जवानों के विकास हेतू ताऊ ने विशेष रूप रेखा बनाई। कुश्ती के खेल के प्रति उनकी विशेष रूचि थी। हरियाणा प्रांत में वर्ष 1978 में प्रथम बार मुख्यमंत्री बनते ही उन्होने करनाल पुलिस लाईन में कुश्ती खेल नियमावली के अनुसार गद्दों पर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता करवाई। वार हीरोज मैमोरियल स्टेडियम अंबाला कैंट में प्रथम बार कुश्ती को राज्य खेल घोषित किया। इसी प्रकार वर्ष 1989 में हरियाणा पुलिस विभाग में सिपाही से लेकर इंस्पैक्टर तक के पदों में 3 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया और प्रथम बार पूरे राष्ट्र में सुचारू तौर से खेल नीति बनाने की रूप रेखा तैयार की। इस नीति को आगे बढ़ाते हुए उनके सपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री श्री औमप्रकाश चौटाला ने एक विधिगत खेल नीति अपनाई और सभी सरकारी विभागों में खिलाडियों के लिए 3 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया। इसी कारण हरियाणा आज पूरे राष्ट्र में खेलों में प्रथम नंबर पर है। इसी प्रकार पुलिसकर्मियों की समय बद्घ पदौन्नति का प्रावधान किया। यही नहीं 15 से 18 वर्ष की सर्विस के बाद सिपाही को हवलदार पद पर पदौन्नति का नियम बनाया। इस प्रणाली को आगे बढ़ाकर श्री औमप्रकाश चौटाला ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2000–2005 में 30–35 वर्ष की सर्विस वाले कर्मचारियों को पुलिस उपनिरीक्षक तक समयबद्घ पदौन्नति करने का प्रावधान किया। अतः आज हरियाणा प्रांत में सिपाही समयबद्ध तरक्की के आधार पर उप निरीक्षक के पद तक सेवा निवृत होता है जो कि पूरे राष्ट्र में एक अनुठी पहल है।

दूसरों के गम में शरीक होना और यथासंभव मदद उनकी फितरत थी। प्रदेश में बाढ़ आ गई तो रिंग बांध योजना बनी और आनन–फानन में कसी तसला लेकर खुद पहुंच गए तथा यह योजना आज तक कारआमद है। तदोपरांत बाढ़ ने कभी राज्य में नुकसान नहीं पहुंचाया। हरियाणा के हिस्से का पानी लेने हेतू फैसला भी करवाया। उस वक्त पंजाब से अकाली नेता उनके साथ रहे जो बाद में राजनैतिक कारणों से यह फलीभूत नहीं हो पाई लेकिन हरियाणा में इस कार्य की परिणिती में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे वास्तव में जन नायक थे। गांव में चौपाल की स्थापना और वहां हुक्का की व्यवस्था करना तथा गांव के विकास हेतू मैचिंग ग्रांट आदि अनेकों योजनाओं के वे जनक रहे।

छोटे काश्तकारों को उनका अधिकार दिलाने हेतू पंजाब विधानसभा में भू–पट्टेदारी अधिनियम 1953 बनवाकर मुजारों की बेदखली को रोका गया। इस अधिनियम के द्वारा 6 साल से भूमि काश्त कर रहे मुजारों को अदालत के माध्यम से आसान किश्तों पर जमीन खरीदने का अधिकारी दिलाकर मालिकाना हक दिलवाया। इसके इलावा उन्होने अपनी खुद की अधिकतर पुस्तैनी जमीन मुजारों व छोटे काश्तकारों को काश्त करने के लिए स्थाई तौर पर आंबटित कर दी थी। वे जन साधारण के कल्याण व उत्थान के लिए आवश्यक मूलभूत कल्याणकारी नीतियों के सुत्राधार रहे हैं। सारे राष्ट्र में उन्होने गरीब, किसान व शोषित वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार की समाज कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी जिसका बाद में केंद्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने अनुसरण किया है।

उन्होने हरियाणा बनने से पूर्व आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किए। वे अपनी दूरदर्शी व पारदर्शी सोच के द्वारा हर प्रकार की समस्या का समाधान निकाल लेते थे। राष्ट्रहित में किसी भी राजनैतिक व सामाजिक मुद्दे पर वे अपने विरोधियों तक से भी सलाह मश्वरा करने में संकोच नहीं करते थे। अपनी निष्कपट, निस्वार्थ व त्यागी छवि के कारण वे समस्त राष्ट्र में 'ताऊ' के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका मानना था कि गांवों के विकास के बिना राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि शहरों की समृद्धि का मार्ग गांवों से होकर गुजरता है। इसलिए अपने शासनकाल में ग्रामीण मजदूर व काश्तकारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया। किसान कामगार व ग्रामीण मजदूर के हितों के प्रति उनके प्रयासों को देखते हुए स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के प्रति इस प्रकार से विचार व्यक्त किए – ''चौधरी देवीलाल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो कि दूसरों को आगे बढने के लिए सदैव गतिशील व मार्गदर्शक हैं, उनके व्यक्तित्व में एक खास .ढ़ता है और संघर्ष ही उनका जीवन है लेकिन उनके

हम आजाद तभी पाते हैं, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। –रवीन्द्रनाथ टैगोर

हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम व सहानुभूति का गतिशील आवास है। हरियाणा प्रांत के हितों के प्रति सदैव सचेत चौधरी देवीलाल को संपूर्ण राष्ट्र के भविष्य की भी चिंता सताई रहती है।''

लेखक को उनके दलित प्रेम का नीजि ज्ञान है क्योंकि सन् 1986–87 में स्वंय उन्होने दलित वर्ग से संबंधित एक आई०ए०एस० (सेवा निवृत) अधिकारी श्री .पा राम पूनिया को राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया और प्रथम बार उनको विधायक बनाकर हरियाणा में सबसे प्रभावशाली कैबीनैंट मंत्री बनावाया और बातचीत में कहते थे कि एक दिन श्री पुनिया को देश का राष्ट्रपति बनाकर अपना संकल्प पूरा करेगें। अपनी इसी सोच के आधार पर उन्होने अनुसूचित जातियों व दलित वर्ग से अनेकों भाईयों को राजनीति में प्रवेश करवाया–जैसे कि नारनौल से श्री मनोहरलाल सैनी व भिवानी से श्री जय नारायण प्रजापति को सांसद बनवाया। इसी प्रकार कलायत विधानसभा क्षेत्र से श्री बनारसी दास बाल्मिकी, घरोंडा से श्री पीरू राम जोगी, टोहाना से श्री आत्माराम गिल आदि को विधायक बनाकर विधानसभा में प्रवेश करवाया। उन्होने हमेशा मजदूर व किसान वर्ग की आवाज को बुलंद किया और उनकी यह अवधाराणा थी कि राजनैतिक ताकत हासिल करके ही किसान–मजदूर का जीवन सुधारा जा सकता है। हरियाणा राज्य को प्रथम प्रांत का दर्जा दिलवाने में चौ० देवीलाल का विशेष योगदान रहा है। उन्होने आल इंडिया हरियाणा एक्षन कमेटी गठित करके पंजाब सरकार व केंद्रीय सरकार के समक्ष भाषा तथा अन्य राजनैतिक आधार पर अलग प्रदेश के पक्ष में दलीलें पेश की और कड़े संघर्ष के बाद हरियाणा प्रांत को अस्तित्व दिलाने में सफलता प्राप्त की।

आज आवश्यकता है कि ताऊ देवीलाल की नीतियों व सिद्धांतों का अनुशरण किया जाए। इससे सरकारी नीति व कार्यशैली निर्धारण में मदद मिलेगी। चौधरी साहब की जन कल्याणकारी योजनाओं व निश्छल राजनीति से प्ररेणा लेकर प्रशासनिक व राजनैतिक तंत्र की विचारधारा को बदलने की नितांत आवश्यकता है ताकि ग्रामीण गरीब–मजदूर व किसान वर्ग के कल्याण व उत्थान के साथ–साथ स्वच्छ प्रशासन के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। वास्तव में ताऊ देवीलाल गरीब व असहाय समाज की आवाज को बुलंद करने वाले एक सशक्त प्रवक्ता थे इसलिए आज जन साधारण विशेषकर ग्रामीण गरीब–मजदूर, कामगार व छोटे काश्तकारों को अपने अधिकारों व हितों के प्रति जागरूक करने की आवश्कता है ताकि दलगत राजनीतिज्ञ व संबंधित प्रशासन इनके हितों की अनदेखी न कर सकें तभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक स्वावलंबी व स्वस्थ ग्रामीण समाज का सपना पूरा किया जा सकता है। अतः एक उदार हृदय एवं महान आत्मा – ताऊ देवीलाल को लेखक सदैव नत मस्तक होकर प्रणाम करता रहेगा।

लेखक 1977 से 1979, 1987 से 1989 तथा अगस्त–सिंतबर 1999 से 2001 तक चौधरी साहब गुप्तचार विभाग के अधिकारी तथा पुलिस प्रमुख रहे हैं।

डॉ0 महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति एवं
जाट सभा, चंडीगढ व पंचकुला

Churchill , Mahatma Gandhi and Act of 1935

R. N. Malik

Mahatma Gandhi had three powerful political opponents after 1930. They were Winston Churchill, Ambedkar and Jinnha. But Jinnha had tremendous personal regard for Gandhi Ji and never used unkind words against him. Their only bone of contention was between divided and united India. But Churchill and Ambedkar were unsparing in their criticism of Gandhi Ji and made very pungent remarks against him. Churchill was more vocal and virtually launched a campaign of calumny and slander against him. He crossed all limits of human decency in his diatribe against Gandhi Ji. Gandhi Ji possessed many rare qualities of human character. One such quality was that he never got frustrated. Secondly, he never indulged in tit for tat policy with his rivals and remained unruffled even in the face of his harshest criticism. At times he smiled at the observations made by Churchill against him. He totally ignored both Ambedkar and Churchill and never responded to their criticism even in writing though he had an insatiable hunger for writing letters.

Churchill's war of words against Viceroy Lord Irvin and Gandhi Ji started when Irvin made the famous statement on 31st October 1929 that ultimate aim of constitutional development in India was to attain Dominion Status. Irvin had taken a great political risk in making this statement and Congress and Gandhi Ji unwisely did not make common cause with Irvin, Prime Minister Mac Donald (heading sympathetic Labour government) and equally sympathetic Stanley Baldwin (heading the Tory party of die-hards) to march on the road leading to Dominion Status: an Ante--chamber to independence. His old friend Henry Pollock advised Gandhi Ji not to waste that opportunity as the Labour Government under Mac Donald was most sympathetic to Indian cause and need of the hour was to have a step by step approach and if Dominion came, independence could not remain far behind. But Gandhi Ji was under tremendous pressure from rising semi-radical leaders like Jawaharlal and Subhas Bose to press for Purna Swaraj and did not act on the sane advice of Pollock. Demand for Purna Swaraj was justified but premature. Ultimately India got Dominion Status on 15th August and not Independence in true sense of the word. Sovereign independence was declared on 26th January 1950.

Soon after the declaration made by Irwin, Churchill wrote an article in Torry newspaper 'Daily Mail' on 16th November 1929. The article made a scathing attack on the policy of constitutional development of India by Labour government in England and Irwin following that policy in India without any demur. He wrote that granting Dominion Status to India was nothing less than a crime and gave all the reasons why perpetuation of British rule in India was essential and advantageous both for India and England. Part of the article is reproduced below.

" Rescue of India from ages of barbarism, tyranny and internecine wars and its slow but ceaseless forward march to civilisation constitutes the finest achievement of our history. Thanks to the British, war has been banished from India, her frontiers have been defended against invasion from the north; famine has been gripped and controlled, justice has been administered, equality between race and race and impartiality between man and man maintained. Scientific education has produced young scientists, technocrats and doctors to ensure future progress of India. All this has been achieved by the willing sacrifices of the best of men of England working in India.

But now this legacy has been threatened by a growing lack of confidence both in England and in India and the undermining repercussions of these doubts upon British officials in India. Out of these doubts has come a plan to hand India over to a Hindu elite with their veneer of European politics and philosophy so that this continent could become the helpless victim of their utopian dreams and predatory appetites and subversive movements (a reference to the campaign of Congress under Gandhi Ji). Dominion status must never be given to a society that does not deserve it. Certainly that exalted status is not suitable for a society that branded sixty million of its inhabitants as untouchables whose very presence is deemed as pollution and who have been subjected to fierce racial indignities and for whose welfare we are responsible. Therefore this criminally devious plan demands the earnest resistance of the British nation in order to safeguard the life and welfare of people of Hindustan."

The article sent shockwaves across the Torry party. But Leo Amery, the contemporary of Churchill in the party, was not impressed. Amery's views were in tune with the views of Irvin. Both opined that it was the time for Empire to modernise itself and accommodate the nationalist urges of the people of India and ultimately the mission in India should come down to a lasting bond of common heritage and friendship between the people of India and England. Amery called Churchill still living in a period of 25 years before..

The declaration of Irvin on 31st October had not given a timeline to grant Dominion status to India. Nor it had talked of its status whether it would be full Dominion status like Canada or Australia or a Dominion status with Viceroy having some special or veto powers. Division of powers between the Viceroy and the government was a matter of negotiations in the proposed Round Table Conference to be held after the publication of Simon Commission report. Irvin unwisely did not realise that one year time distance was too far and Congress and other political parties had become restive to demand for Swaraj. Another folly of Irvin was not to call an all party meeting to conciliate for the success of RTC. This initiative was taken up by Congress alone and Irvin did not show his diplomatic skills to make the Congress initiative a success. Four persons understood the importance of the 31st October statement. They were Motilal Nehru, Dr. Ansari, Moderate leader T.B.Sapru and Gandhi Ji. They held a meeting on 2nd November along with Jawaharlal and Subhash. They agreed to go along with Irvin provided Congress was treated as the principal spokesperson to speak for India in the RTC and agenda of RTC would be to grant full Dominion status to India. Jawaharlal and Subhas agreed to this proposal after lot of arm twisting by Gandhi Ji because the new goal already set was Purna Swaraj and not Dominion Status. A meeting was held with Irvin on 22nd December which was also attended by Jinnha. Irvin could not agree to these two stringent conditions at this stage and the meeting ended without achieving anything. Irvin too did not show adroitness and made no effort to find a middle path.

On the other hand, Irvin's statement of 31st October had created a furore in whole of England. British Parliament had never talked of granting Dominion status to India. Even the historic statement of Montague on 20th August 1917 had not mentioned about Dominion status. Consequently, on 8th November, Tory M.P.s were at their feet to question the authority of Irvin to make that declaration in the Parliament. Churchill arrived from America on 5th November. He was already in a foul mood as he had lost lot of his savings due to Great Crash in the Wall Street in New York. He was cut to the quick when he heard of the Irwin declaration. He arrived in the Parliament in a very combative mood. According to one observer, he was demented with fury. Both Baldwin and Mac Donald had to strain themselves to defend Irvin in the Parliament. That is why Irvin had told Gandhi Ji that he had taken a great political risk in making the 31st October declaration. Gandhi Ji should have realised the discomfiture of Irvin and the Prime Minister. The problem with Congress were two. Firstly it did not have a clear headed and sagacious leader like Lokmanya Tilak. Gandhi Ji excelled in other attributes but was a poor politician and a manager because of his sainthood. Secondly, Gandhi Ji and Congress did not possess a synoptic view of the entire situation and did not know what view was being taken in England and the Parliament about the Indian question. What ultimately mattered was British Parliament and obviously it could not be bypassed. Viceroy was only an Ambassador of that Parliament.

Congress annual session was held on the banks of river Ravi near Lahore where it was declared that not Dominion status but Purna Swaraj was the ultimate aim of Congress. No timeline to attain Purna Swaraj was set at the session and the issue was left open ended. The issue on how to snatch the Purna Swaraj from powerful British Empire was discussed slightly. Only Subhas, Sardar Patel and Dr. Ansari gave their views. Neither Motilal Nehru nor his son-- the President of the party made any suggestion. Finally Gandhi Ji of his own launched the Salt Satyagraha on 12th March 1930. It was no substitute for Satyagraha for attaining Purna Swaraj. All the leaders along with 90000 Congress workers went to jail. Most of them were bread earners for their families. Irvin released Gandhi Ji and other members of Congress Working Committee (CWC) on 26 th January 1931. On 23rd January, Subhash was sentenced to one year imprisonment on the charge of taking out a procession on the occasion of death of Jatin Das in August 1930. Talks were held between the Viceroy and Gandhi Ji for 17 days between 17 th February to 5 th March 1931 to stich the Gandhi -Irvin pact. Being a proven poor negotiator, Gandhi Ji got nothing from the pact except that Satyagrahis were released, unsold confiscated lands to be released, residents of coastal villages allowed to manufacture salt from the sea and Gandhi Ji to attend the 2nd RTC to be held after six months. Gandhi Ji was thoroughly outfoxed by Irvin through the art of flattery. All the members

of CWC were disappointed beyond measure when they read the pact as it spelt a total come down from the original stand of the Congress. But they could not revolt against the Bapu and passed a resolution of total agreement with the pact.

Churchill was not sitting idle during this period. His friend Harold Nicholson found Churchill a thoroughly dispirited man and started feeling as if he had lost his old fire power of an enfant terrible.This happened in January 1930. But as the news of Salt Satyagraha started reaching England, Churchill started recovering his old power of clashing with his opponents. Like Curzon, he was very possessive of India and knew that independence of India would mean a great economic loss to Britain. He thought that a sustained campaign against granting Dominion status to India would rehabilitate him politically and to break even with the party head Stanley Baldwin and finally to take his seat. So anti-India campaign became his pet theme for next five years and he fought very fiercely against his own party members on this issue.

In September 1930, Irvin sent Sapru, Jayakar and Motilal Nehru (from Lucknow jail) to bring around Gandhi Ji to start negotiations with the Viceroy. Gandhi Ji disagreed. Finally he was released in January 1931 and negotiations were held in February next year. When Churchill heard about this negotiation process, he flew into paroxysms of rage. He accused Irvin ," You have allowed this malevolent fanatic to hold consultations with fellow conspirators and emissaries of the government.You are sending wrong signals as if government is clearing out of India. You are now fighting only a rearguard action. Turmoil and violence will be the natural outcome." Simon Commission gave its report in July 1930. It made two proposal. Firstly provincial governments would have full powers to run the provincial administration. The central government too would be run by Indians under a strong Viceroy with complete control over departments of Defence and Police. Irwin was annoyed because the term 'Dominion status ' was not used in the report and had recommended only diarchy at the central level. Consequently Irvin announced the dates of RTC and did not call Sir John Simon as an invitee. Churchill and his die hard friends like Llyod George (not the Prime Minister of England during Ist World War) termed this whole process as 'Give Away India'. Churchill remarked," Now Irvin and his Socialist allies are about to use this so-called RTC to hand India over to a clique of politically minded and highly educated Hindus who would reduce India to the deepest depths of Oriental tyranny and despotism." Such statements of Churchill sent alarm bells into the party offices. But most members disliked such pungent statements. George Lane Fox called these statements as inflammatory and reprehensible.

Those who formed Churchill's team to put spokes in the constitutional development of India with equal vehemence were John Simon, Lord Reading (predecessor Viceroy of Irvin in India), press barrons (Beaverbrook, Rothermere and Lord Burnham), Field Marshal Sir Claude Jacob and many more army officers. George Llyod said," How much British rule has improved the lives of Indians and how minorities like Muslims and untouchables relied on the British to protect them from Hindu Brahmin elite. Therefore giving away India will not be progress but a step backwards towards the old early days of lawlessness when British arrived and brought law and order and civilisation." Many Liberal M.P.s feared about India without British authority. Reading accused Irvin of pursuing a 'Policy of Appeasement'- a policy never tried earlier. The danger is that after the sacrifices made in many wars in India, we are throwing away our own conquests and inheritance." Another Army officer remarked ," We are galloping down in Bombay and elsewhere."

The first Round Table Conference started its proceedings on 11th November 1930 in London. 16 Britishers and 56 Indian delegates attended the Conference. Gandhi Ji had already boycotted the Conference. All the minority representatives were vying for their voices in the new set up. Finally all the delegates revolved around one proposal I.e. constitution of All India Federation with statuary safeguards for each minority group so that dominant groups could not subdue or swallow the weaker groups. Gandhi Ji called the Conference as Hamlet without the Prince. He also remarked that Federation scheme was not acceptable as British power to rule India remained intact and it was not a case of transfer of power. This way the first RTC did not collapse simply because Congress did not attend it. The Secretary of State Wedgewood Ben got the idea of what the Indians largely wanted. Jinnha and Princes also agreed to the proposal of All India Federation with constitutional safeguards for minorities. Consequently the British government started working further to translate the idea of federal government into reality.

On 11 December 1930, India Empire Society of England held its first major public meeting at Cannon Street. Churchill was the main speaker. He thundered," From many corners, we are hearing that opinion on India is advancing with a violent speed. Full Dominion status with the right to secede from the British Empire is being clamoured from all sides. But I may tell you that any agreement reached at RTC will not be binding morally or legally on the Parliament. Only Parliament has the power to have a final say on the future of India. The British nation as we believe, has no intention of relinquishing an effective control on Indian life and her progress. The western educated elites who aspire to bear no relation to the aspirations of millions of faceless poor, untouchables and minority groups. As a result, they would be subjected to Hindu despotism. If British Raj is replaced by Gandhi Raj, then rulers of princely states will be stripped of their powers and minority groups will lose their rights. If Lahore Congress were broken where Union Jack was burnt and its leaders deported and Gandhi had been arrested and tried as soon as he broke the Salt Law, then three- quarters of distress sweeping India could have been avoided. But weakness at the centre and defeatist policy of our politics has made Gandhi and Indians believe that we are leaving India. The truth is that Gandhism and what it stands for will have to be grappled and crushed sooner than later. There is no use of trying to satisfy a tiger by giving a cat's meat. Sooner this is realised the better. The only alternative is that we should accept the the downfall of British empire." The speech was given a thunderous applause many times by the audience.

The speech received widespread coverage in the press. Most readers criticised Churchill for further complicating the Indian issue. Geoffrey Dawson, editor of London Times, too criticised Churchill for delivering a speech that exposed him more than Irvin or Gandhi and he was still living with his old memories of the past. Irwin called the speech as monstrous. He said, " Practising Churchill's kind of imperialism was like trying to fly a balloon that won't hold gas. This won't work."

Churchill's outrage shot up very high when he learnt that Gandhi Ji was released on 26th January 1931 and Irvin was having parleys with him after six weeks. He remarked," The tired old man has been transformed into a human dynamo. Earlier in January, he wrote to his

son Randolph," Both Reading and Llyod George have signed the proposal for holding next RTC to discuss Indian Federation scheme but I am going to continue to fight that Indian business and defeat 'Irvinism' once and for all." When Gandhi Ji was released on 26th January, Churchill rose in the House of Commons and blasted the government for agreeing to hold another RTC. It was unprecedented that Sovereign Power which had created modern India was negotiating with Gandhi to hand over the title deeds of British position in India. Gandhi is again at large and he will make every Indian believe that British Raj was about to be replaced by Gandhi Raj. The great liner is sinking in a calm sea."

The Torry M.P.s greatly cheered Churchill at the end of his speech and they started worrying about the future of England without India. Speech of Baldwin could not match that of Churchill. But he did not budge and announced that if Tories came to power in the ensuing elections then agreements reached in the RTC would be faithfully implemented. Finding the attitude of Baldwin as defiant, Churchill resigned from his Business Committee. He addressed another rally of mill workers at Manchester on 30th January. There again, he thundered," Your fortunes depend upon India as an outlet for exports. The declared determination of Gandhi to exclude for ever all foreign goods would mean the ruin of Manchester and Lancashire. The loss of India will be final and fatal for Britain but also for India. The future of England and India will have to be safeguarded against the likes of Gandhi. He is a fanatic and an ascetic of the fakir type well known in the East whose incarnation has made him a martyr under very comfortable conditions and a national hero without any risk. With his release, he now emerges on the scene a triumphant victor. A British withdrawal will leave India in his clutches and in a very short time Gandhi and his friends would reduce their country to the kind of anarchy in which China finds itself." Again Churchill's speech reverberated the hall. After receiving ovation at Manchester, Churchill started believing that party might replace weak Baldwin with him. Supporters of Baldwin too were complaining about his uninspiring stand on Indian issue and rising exuberance of Churchill.

Churchill had been telling the press that he was not going to let India be betrayed without telling England all about it. Frightened Amery wrote to Baldwin," Winston has chosen his moment and his excuse for separating from the party very adroitly." More fiery speeches followed at Tory meetings and his momentum and clout started growing day by day. He heaped scorn on Irwin striking a private deal with that malignant subversive fanatic. On 23rd February, Churchill made the notorious but famous remark about Gandhi Ji.

" It is alarming and also nauseating to see Mr. Gandhi, a seditious Middle Temple lawyer now posing as a fakir of a type well known in the East, striding half naked up the steps of the Viceregal palace, while he is still organizing and conducting a campaign of civil disobedience, to parley on equal terms with the representative of the King Emperor. Such spectacle can only increase the unrest in 'India and the danger to which white people there are exposed."

Two newspapers-Daily Mail and Evening News were also busy in building Churchill's image. London Times was on Baldwin's side to counter Churchill influence. Still confidence level of Churchill went very high. But suddenly luck smiled on Baldwin and Irvin. The Gandhi--Irwin pact was out on 5th March. It offered nothing to Gandhi Ji and he went empty handed swallowing his self pride. This pact made all the fears (of sell out on India) expounded by Churchill look mere figments of his imagination or deliberately trumpeted just to belittle Baldwin. Churchill had said worse things about Gandhi Ji. However Gandhi Ji was amused when he came to know about all the bunkum and rubbish Churchill had thrown at the doors of Gandhi Ji.

Finally the showdown between Baldwin and Churchill came on 12th March,1931.The occasion was the debate in House of Commons on the subject 'Government's policy on India'.The contest between Churchill and Baldwin was also for the leadership of the Tory party. Baldwin knew about the pyrotechnic skills of Churchill as a speaker. He had also confessed," No party is as divided as mine. Sam Hoare is a timid rabbit....Oliver Stanley has cold feet....It is a party of fools." But Baldwin was fully prepared. Churchill and his allies had spent their lives in underestimating Baldwin. He would prove them wrong again.

Churchill gave a long stormy speech raging against the proposed RTC and the invitation extended to Gandhi. There was nothing new in his speech in the House of Commons except repetition of old charges and play of words. For example, he said," Thanks to Irwin, Gandhi has become the symble and Godlike champion of all those forces which are working for our exclusion from India...Irwin had tried to bargain with Gandhi when he was still in Yeravada jail. Then he finally released him unconditionally and opened negotiations with Gandhi as if he were the victor in some war-like encounter instead of a criminal and a miscreant. Irvin has converted what should have been Gandhi's ignominious defeat into a trophy of victory."

Churchill's speech was good but Baldwin's speech was better. Thomas Jones called it the speech of his life. Baldwin said," The unchanging East has changed. The world needs to recognise the power of Indian nationalist sentiment. We have impregnated India ourselves with western ideas like national liberty and self governance. We are now reaping the fruit of our own efforts. All India Federation Plan is the best proposition to ensure self government with India remaining integral part of Britain. Lord Irvin has made a super human effort to have the Gandhi-Irvin pact. Churchill had himself said after Jalianwala massacre that our reign in India should not be based on force but on constructive co-operation and goodwill. We are doing exactly the same. Gandhi-Irwin pact is based on that sentiment and Churchill has no basis to be critical of our policy on India. If members of niggling spirit are in majority in my party, they can have a new man to lead them. Otherwise they should help us for smooth advance of constitutional development."

Churchill spoke after Baldwin but it was too late and the leadership of Baldwin was now stamped with authority. Churchill said," Granting Dominion status to India means empowering Brahmin oligarchy that will grind Muslims and untouchables into dust. It is our duty to protect the minorties and I shall continue to carry on my fight till end." But members of almost all parties scoffed at Casandra-like prophecies of Churchill.

The Secretary of State made no effort to give a concrete shape to the the All 'India Federation Plan' during the last six months I.e. from March 5th to 5th September 193l. Gandhi Ji reached England on 12th September to attend the second RTC. He was given a standing ovation by thousands of people when he reached Folkestone. There was hardly a place where he was not given the rising reception during his 85 days of stay in England. Charlie Chapline also came to see him and this meeting between two greats was no less than a cosmological

event. But this ovation of Gandhi Ji created no special effect on the mindset of British M.P.s. They still considered him as an astute crafty politician of his own type and mind. There was no meeting point between Gandhi Ji and Samuel Hoare -the Secretary of State for India. Gandhi Ji wanted Independence first and solution of communal question later. British government wanted to settle communal question first and Federal government later. Gandhi Ji did not deliver a well prepared thundering speech. People of England and media were expecting a soul steering speech from the lips of the world renowned great man. But no such thing came out and all of them were greatly disappointed. The discussions became Gandhi Ji versus the rest. Gandhi Ji came thoroughly unprepared to attend the Conference. He started working on his spinning wheel whenever he got spare time. He talked of independence and an equal partenership with England. He met Hoare and Prime Minister MacDonald twice and the four meetings were a flop show.

The Conference was over on 1st December. Gandhi Ji made it plain that India would have to strive to win independence by using well tested weapon of Satyagraha. Hoare also gave a hint that he too should be ready for arrest. Hoare and Viceroy Willingdon were in constant touch with each other. Gandhi Ji left England on 5th December after having a final meeting with Hoare and Prime Minister Mac Donald. There too he did not talk with them with an open mind to devise a middle path so that it could be a win-win situation for both sides. To snatch independence from England through Satyagraha of Gandhian type and without the support of Muslims, Dalits and Princes was well nigh impossible at that stage and British government knew it. What he was being offered now was without any risk taking and almost free.

Proceedings of the RTC were discussed in the Parliament on 3rd December. Churchill again thundered in the House of Commons for 90 minutes with his old cliches against Irwin and Gandhi Ji. He said that Parliament was not bound by the decisions arrived at the RTC." The concessions given to Indians everytime have made India more unstable and ungovernable. The proposal to make India a United States of India without the plans of amalgamating the princely States with the provinces and protecting the minorities will lead to chaos. Also by letting India away, you will be simply undermining the great historical position of England in the East." The thundering speech of Churchill had little impact on M.P.s. Once again Baldwin prevailed and Churchill's attempt to amend the resolution got only 46 votes. Llyod George met the same fate in the House of Lords.

Gandhi Ji reached Bombay on 28th December. India was again having turbulence in different parts. Hoare had asked the Viceroy to be tough with Gandhi Ji. Gandhi Ji wrote to the Viceroy that Congress would not tolerate political terrorism. Making this letter as the base, Viceroy ordered the arrest of all the Congress leaders. Congress party was declared as a banned organisation. India became as calm as the sea after three months of the crackdown. Churchill praised Willingdon for his courageous act. Hoare had realised that two powerful persons were the roadblocks to his scheme of Federal India I.e. Gandhi and Churchill. Now one had been tamed and another remained to be tamed. Now Hoare planned to draft a full fledged Indian Act of federal structure. It consisted of three steps.

1. Granting full autonomy to provincial governments.

2. A formula will be worked out to calculate the number of seats to be reserved for different minority groups and provide separate electorates for Dalits. So all groups will be happy to get constitutional safeguards and agree for the Federation Plan.

3. Princes will be allowed to send their nominated representatives in the Central government in proportion to their population I.e. 33%. The Viceroy will be invested with reserve powers to run the departments of Defense, Police and Foreign Affairs. Thus India will remain an integral part of Britain.

With these provisions in view, Hoare thought, India would be given to Indians for self governance and they would largely accept the new Act without any demur and Churchill too would be silenced. Consequently, Hoare started drafting the new Act and carrying its journey through difficult and narrow parliamentary channels.

With Gandhi Ji in jail, Churchill had to concentrate his attack on Baldwin only. Irwin too went out of picture as Gandhi-Irwin pact was no longer the issue. Baldwin and Hoare too had to face only Churchill. So a direct fight was in the offing. The first round of fight was over. The second round started in October 1932 when Conservative Party Conference was held at Blackpool. Churchill could not come as he had an attack of paratyphoid at his home in Chartwell. So it was Lloyd George who led the opening salvo against the government's Indian policy with a resounding speech that drew a prolonged and enthusiastic applause. It appeared as if the entire party was on his side.Then came the turn of Hoare. He and another young member Rechard Butler produced an equally powerful counter blast in their respective speeches. Now all the members were convinced that Baldwin and Hoare were fully determined to carry forward their agenda to the logical end. The members did not want to create a wide rift in the party on this issue. Hoare also gave a hint that if the Bill was turned down at this stage then Labour government in future would come up with a far bigger give away plan down the road.

Politics is not always the art of the possible. It is sometimes the art of choosing between the distasteful and the disastrous. Consequently, the party backed Baldwin and the government and Churchill saw the handwriting on the wall.

As the year 1933 came and went, an alarmed Churchill worried that 'creeping Irvinism' had rotted the soul of the Tory party. He knew that Baldwin and Hoare had mobilised the entire party machinery to support the India bill. He exclaimed,"Still it is our duty to fight with every scrap of strength."

The House first debated a motion to limit Indian government reform to the provinces only and Churchill could muster only 42 votes in his support. National Union of Conservative Associations held its meeting in February 1932. Churchill again delivered one of his best speeches. But Diehards lost again by 25 votes. In March 1933, the government issued the White Paper recommending that a Joint Select Committee draw up an Indian constitution. Churchill again launched a tirade attacking the idea of self government in India and its timing. He said," Where is the need to rush through this legislation when Gandhi is in jail and India is at peace. You cannot desert and abandon the toiling faceless millions. They are as much our children as any children can be. It is impossible that you should hand them over to the oppressor and to the spoiler and disinterest yourself in their future." But that was what the House of

Commons did. At the end of three days debate, the vote was in favour of recommendation by 475 to 42. Churchill commented," I shall fight this business to the end. A disappointment only makes me fight harder."

On June 28, he carried his fight to the Conservative Central Council which had been called upon to pass a resolution approving the coming Indian bill. Churchill told the delegates,"Surrender on India meant surrender everywhere. The way we handle this question here will have far reaching repercussions on all our possessions elsewhere." The final vote was 838 yes and 316 no. Churchill's opposition was slipping away fast but he won't leave his dogged and dogmatic fight. Fortunately, he and Lloyd George refused to serve in the Joint Select Committee to draw up the bill. Lord Linlithgow, the next Viceroy of India, was the Chairman of the Committee. Every member of the party felt that wild criticism had become the second nature of both Churchill and Lioyd George. Hoare commented," Churchill wants to govern India like Mussolini rules Africa." Churchill had brought self-government in South Africa and Ireland and so why not in India. Churchill replied ," India is unsuited to democracy because of its cultural backwardness and widespread illiteracy." But many suspected that real reason for his resistance was racial as he had once said that it was never possible to make concessions to Orientals.

Mirabehn (Madeleine Slade) met Churchill in September 1933. Churchill told her that proposed India bill neither pleases us nor you. It falls between two stools as it is not backed by people of India for whom it is meant .(This is what Gandhi Ji said once.). A kind of fellowship of Hindus, Muslims and Christians with a strong Centre to hold it together would have been the right choice." Churchill also spoke some kind words about Gandhi Ji.

Drafting of Bill by Joint Select Committee took 18 months. In January 1935, the government introduced its Government of India Bill. It was tremendously long -longest Bill Parliament would ever pass. Over the next six months, it would be subjected to countless amendments and many hours of tedious debate. But it's basic structure never altered. The Bill had three basic features.

1. The Bill provided India the Dominion status through an All India Federation that excluded Burma but included princely States. One third members of Federal Legislature would be nominated representatives of the ruling princes and remaining members would be elected representatives of provincial India. A British Viceroy would remain with certain 'reserve powers' at the centre such as over the army and the police. He would also be able to raise taxes to finance them. But otherwise India would be governed by Indians themselves. The Bill signalled the end of the Raj and the begining of the self-governing Dominion of 'India.

2. The Bill set up an entirely autonomous provincial administration and governance for Provincial India. Almost a sixth of population was allowed to vote its representatives in the provincial Assemblies. For the first time in India, Indians would become the Premiers (presently Chief Ministers) to rule the provinces with their choicest members in the Cabinet. The Governor-General would have only a perfunctory role.

3. A formula was worked out to provide reservation of seats for various minority groups.

For five long years, Churchill and his allies had fought a delaying action against the Bill. Churchill denounced the Bill in a radio speech," It is a monstrous Bill erected by pigmies and its passage will be a catastrophe that will shake the world."

The Bill faced its second reading on 6th February. The House's impatience to finish with the business and anger at Churchill for his delaying it became palpable. Opening speech of Hoare was scathing in its denunciation of Churchill's tactics. On 11 February, Churchill made one last speech to try to halt the end of an epoch. He declared," We are now at the fag end of these long debates on India. How shall we come out? No one can tell." He continued with his usual dark prophecies. Voting was done. Churchill received 133 votes (including 84 Tories and 49 naysayer radical Labourites who felt that reforms did not go far) against 404 in favour of the Bill. The passage of the Bill was now a certainty. On 21st, an amendment by Churchill was also defeated overwhelmingly by 308 to 50. Churchill commented," One of the most melancholy, one of the most perverse, one of the unnecessary chapters in whole history of British people to become law." The third and final reading came on 4th June. The government secured 264 votes against 122. Churchill again became the prophet of gloom when he said," I hope the Bill will not sound the death knell of Brtish Empire in the East."

At the end Churchill expressed his desire to forget and forgive the bitterness of the preceding few years. He wished well for everybody except Hoare. He kept him at a distance during his prime ministership after 1940. He invited G.D.Birla for lunch at his home and praised Gandhi Ji for his social projects and his untiring work against the scrouge of untouchability. At the end of the lunch, Churchill said," Tell Mr. Gandhi to use the powers under the Act and make the new Act a success. He was sorry that he did not meet him when he was in England. I should like to meet him now. I will love to go to India before I die." But after the passage of the Bill, Churchill became a perfect back bencher in the Tory party till his fortunes were revived in 1940 after the tragic failure of Peace Treaty of Neville Chamberlain in 1939.

Elections were held in February 1937 under the 1935 Act and Congress secured absolute majority in U.P., Central Province, Orrisa, Maharashtra, Madras and North-West -Frontier-Province. Unionist Party came to power in Punjab. Sir Sikander Hyat Khan was elected as the Premier of Panjab. Ch. Chhoturam became the Minister in his cabinet. G.B.Pant became the Premier of U.P. Vijay Lakshmi Pandit became one of the Ministers in his cabinet. Coalition ministries were formed in Bengal and Assam. Rivalry between Churchill and Gandhi Ji continued again during the spell of 1940 to 1945 but at a reduced scale.

Had Gandhi Ji and Congress co-operated with Irvin right from November 1929, the Bill would have become the Act much early and Gandhi Ji and Congress workers been saved from the drudgery of living in jails for four long years. Demand for independence could be taken up after successful operation of the Act for few years. However Provincial governments under Congress Premiers did wonderful work for two years. The governance completely matched the concept of Ram Rajya. But start of 2nd World War on 1st September 1939 wholly upset the apple cart. Congress also unwisely rejected the Federal part of the Act largely due to the whims of Jawaharlal and Subhas. In fact, the co-operation with Hoare could have brought a more favourable draft of the 1935 Act. This is the unheard story of the passage of the 1935 Act that allowed Indian leaders to rule the provinces much before 15th August 1947.

चौधरी महेन्द्रसिंह टिकैत से चौधरी राकेश टिकैत तक

– सूरजभान दहिया

देश जब आजाद हुआ, जर्जर आर्थिक स्थिति बदलने के लिये पं० जवाहर लाल नेहरू ने विकास का एक मॉडल दिया जिसे नेहरू मॉडल कहा जाता है। देश की वर्तमान खराब स्थिति के लिये अनेक बुद्धिजीवी जवाहरलाल नेहरू तथा उनके विकास मॉडल को जिम्मेवार मानते हैं। दरअसल सिद्धांततः सभी भारतीय नेता पूंजीवादी समाज और अर्थव्यवस्था की स्थापना के पक्षधर थे। जवाहरलाल नेहरू अपनी इस इच्छा को 'फेबियन समाजवाद' और 'कल्याणकारी राज्य' की चाशनी में लपेट कर पेश करते थे। गांधीवादी चौधरी चरणसिंह इस मॉडल के कतई पक्षधर नहीं थे। वे लाग–लपेट आदमी नहीं थे इसलिये उन्होंने किसान हितो के प्रवक्ता होने का जिम्मा किसी ग्रामीण समाज के वकील के रूप में नहीं बल्कि उभरते हुये पूंजीवादी शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई। एक बार फिर वे ही गलतियां दुहराई जा रही हैं जिनके लिये नेहरू जी की आलोचना की जाती है। गांधी जी के बताएं गए उपायों द्वारा प्रत्येक ग्राम को एक स्वावलम्बी ईकाई बनाने का प्रयास किया जाना चाहियें जिसमें खेती खुशहाली और ग्रामरोजगार पर काफी जोर दिया गया हो। वर्तमान आन्दोलन में सक्रिय राकेश टिकैत कहते हैं – "किसान खेत में लुटता है और उपभोक्ता बाजार में और जो मार्केटिंग व्यवस्था लादी जा रही है उसमें 12 महिने कमाने वाले किसान को बंधुआ मजदूर बना देगा। कारपोरेट जगत के सामने भोला भाला किसान ओंधा गिर कर रेंगता हुआ दम तोड़ देगा। हम भूख का व्यापार नहीं करने देगें।"

लोकतंत्र में राजनीति सबसे प्रबल औजार है। राजनीति में सीजन चलता हैं, आजकल किसानों की बड़ीचर्चा है। यो तो भारत न जाने कब से कृषि प्रधान देश कहलाता है – एक बड़ा किसान आन्दोलन किसानों की समस्याओं को लेकर देशभर में पिछले कुछ महीने से चल रहा है। आर्थिक विषमताओं को लेकर चौधरी चरण सिंह ने गतसदी के अस्सी के दशक में 'इंडिया बनाम भारत' की बात रखी थी। उस समय प्रख्यात अर्थशास्त्री एच.के. परांजये ने माना था कि गांव और शहर को लेकर आर्थिक मोर्चो पर एक लड़ाई तो है। आर्थिक विकास को लेकर गांव हमेशा शहरों पर अवलंबित होते हैं क्योंकि सारी व्यवस्था शहरों से संचालित होती है। उसके आगे कृष्णराज संपादक – इकोनामिक एंड पालिटिकल वीकली ने स्पष्ट किया था कि "पिछले तीन दशकों में शहर और गांव के बीच आर्थिक खाई तेजी से बढ़ी है। हमारे विकास और पूंजीनिवेश की प्रक्रिया ही कुछ इस तरह की रही है कि जिससे शहरों को फायदा तथा गांवों की नुकसान हुआ। खेती में सरकारी तथा गैरसरकारी पूंजीनिवेश लगभग थम गया है। उनतीस वर्षों में राष्ट्रीय आय में गांव का योगदान 60 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत हो गया है जबकि खेती पर आश्रितो की संख्या में कोई उल्लेखनीय कम नहीं है।"

चौधरी चरणसिंह ने आधुनिक किसान इतिहास के चौथे चरण की शुरूआत इस उद्घोष से की थी कि "बहुसंख्यक जनता जो असली भारत में (अर्थात् गांवों में) रहती है को फायदा पहुंचाना है तो विकास के पूरे कार्यक्रम में बुनियादी बदलाव लाना पड़ेगा, इसके लिये संघर्षरत होकर पूर्ण अर्थशास्त्र को किसान ने स्वयं समझना होगा" इस उद्घोष को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत ने अपने ग्रामीण भाईयों को समझाया तथा किसानों को कहा कि अपने हक की लड़ाई लंबे अरसे तक चलानी पड़ेगी। उन्होंने अपने भाईयों को कहा – "देखों! यह कैसा आर्थिक असंतुलन कि गांव के आदमी की आमदनी, शहर के आदमी की आमदनी से आधी से भी कम हैं, दूसरा अभी भी 70 फीसदी लोग गांव में रहते हैं और खेती पर निर्भर हैं लेकिन राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा दिनोंदिन घटता जा रहा है, लोग उतने ही हैं खेती पर निर्भर हैं। खेती की पैदावार बढ़ने के बावजूद राष्ट्रीय आय में अनुपात घट रहा है। तीसरा – गांव में उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं जो जनता है या नई पीढ़ी है वह कृषि में खप नही रही है। युवा पीढ़ी अपने मां–बाप को कोस रही हैं कि वे क्यों निठले बैठे हैं – गांव में क्यों नीरसता है? हम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चौथी बात यह है कि सामाजिक संरचना या सामाजिक विकास के जो माध्यम हैं – शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार वगैरहा उनका विस्तार जितना शहरों में हुआ है, गांव में नहीं हुआ और पांचवा जो चीजे किसान खरीदता है उसकी कीमत ज्यादा देता है और जो बेचता है उसकी कम पाता है। हम रोटी की लड़ाई लड़ते रहे। भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, भीषण वर्षा और बाढ़ झेली है। हमने टीलो को खोद–खोद कर ठीक किया है, सांपो के सिंर कुचले हैं। देश को अन्न के मामले में आत्म निर्भर बनाया है। भूख का कटोरो जो हम विदेशों के सामने फैलाकर शर्मशार होते थे, उससे बचाया है, पर सरकारे हमें अब तिरस्करित कर रही हैं? हमें संघर्ष करना होगा। हम ज्यादातर उपेक्षित नहीं रहेंगे।"

टिकैत जी की ये बाते गांव के धर–धर पहुंची और किसान ने संकल्प लिया कि वह उपभोगता सामग्री नहीं है, उससे भी विकास में हिस्सा चाहिये। चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत बालियान खाप के प्रमुख थे। किसान समुदाय आदिकाल से अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक समस्याओं का निपटान खाप व्यवस्था के माध्यम से करते आ रहे हैं। तत्कालीन

हम आजाद तभी पाते हैं, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। – रवीन्द्रनाथ टैगोर

किसानों के ज्वलंत मुद्दो पर टिकैत जी ने अपने गांव सिसौली में 1 अप्रैल, 1987 को सर्व खाप महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में टिकैत जी ने कहा "अपने हाड–मास गलाकर खेती करने वाला किसान सरकारी नीतियों और प्रशासन व्यवस्था की उपेक्षा के कारण शोषण का शिकार हो गया है, उसे कृषि उत्पादको का न तो वाजिब मोल मिलता है, न उसे वे सुविधाएं मिल रही हैं जो शहरियों को मिल रही हैं, अतएव हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी – लड़ाई तो यह 'लुटेरों' और कमेरो के बीच है।" उपस्थित जन–सैलाब ने चौधरी की बात का समर्थन किया।

तत्पश्चात् टिकैत साहब के किसान आन्दोलनों का लंबा सिलासिला चला, उनके समर्थन में महाकिसान शक्ति थी। टिकैत जी का पूरा जीवन निर्बाध चेतना–प्रवाह की ऐसी अर्न्तकथा है जो अवरोधों को समेटती हुई अनवरत ग्रामीण विकासोन्मुखी रही। उनके जीवन का एक चुनौतीभरा लक्ष्य था। शोषित ग्रामीण समाज को गांधीवादी तरीके से राहत दिलाना। उन्होंने इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु आधिकारियों को ललकारा, डटे रहे, झुके नहीं, अविचलित रहे क्योंकि उनमें वैचारिक गहनता, स्पष्टता और तटस्थता थी – उदात्तयोद्धासी। असली भारत जो गांव में बसता है के वे सच्चे प्रतिनिधि, सादगी के प्रतीक सरलता की साक्षात् प्रतिमूर्ति तथा किसानहितों के सजगप्रहरी थे। उनका किसान हित संघर्ष शामली, मुजफरनगर, मेरठ, लखनऊ से होता हुआ भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा। इस संघर्ष यात्रा में न जाने कितनी बार पुलिस की लाठियों, तेजपानी की बोछारों आदि मुसीबतें झेली, लेकिन वे अंहिसा के पथ पर अडिग रहे। दिल्ली में वोट क्लब की किसान रैली ने उन्हें अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति दिलाई परन्तु वे महात्मागांधी की भांति राजनीति से दूर सच्चे महात्मा रहकर किसान समर्पित रहे – सदैव किसान हितों के लिए विजयी रहे।

चौ० चरण सिंह का जब निधन हुआ तो दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने उनका दाहसंस्कार दिल्ली में करने की अनुमति नही दी। टिकैत जी को यह अस्वीकार्य थी, लाखों किसानो के साथ उन्होंने दिल्ली में आह्वान किया – "दिल्ली किसान की मातृभूमि है और किसान मसीहा चौ० चरण सिंह उस वसुन्दरा के सच्चे सपूत पूत थे, अतएव उनका शरीर इस माटी में विलीन हो गए। यमुना नदी के प्रांगण जो समाधियां बनी हैं, उन्हें हटाना होगा अन्यथा किसान घाट तो बनेगा ही।" अन्ततः टिकैत जी की बात को सरकार ने स्वीकार करना पड़ा – भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौ० चरणसिंह को अन्तिम विदाई किसानों ने किसानघाट पर देकर उन्हें अमर बना दिया।

ऐसे किसान चेतना के पुरोधा टिकैत जी 15 मई, 2011 को अपनी कर्मभूमि, धर्मभूमि और संघर्षभूमि में अन्तिम सांस लेकर अन्नत में विलीन हो गये – सामूहिक किसान संघर्ष के महायज्ञ। चौ० महेन्द्र सिंह टिकैत की विरासत अब उनके बेटो नरेश टिकैत तथा राकेश टिकैत के कन्धों पर है, वे इस दायित्व के प्रति समर्पित हैं।

पिछले कुछ महिनों से किसान आन्दोलन में गाजीपुर बार्डर पर बैठे चौ० राकेश टिकैत को गहरी पीड़ा है कि "सदियों से शोषित किसान पर अब संकट के बादल गहरे हो गये हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है। प्रशासन व्यवस्था में चाहे – बाबू किंग हो अथवा कारपोरेट किंग हो, किसान को दोनों ठगते हैं। संसद में किसान अहित के कानून बनाने की छूट है क्यों कि वहां किसान मसीहा चौ० छोटूराम या चौ० चरण सिंह जैसे सांसद आज नहीं हैं। अब जरा मार्केट का हाल समझिये – कृषि उत्पाद को छोड़कर सभी उत्पाद डैच पर बिकते हैं यानी डंगपउनउ त्मजंपस च्तपबम पर भी बबाल खड़ा हुआ है। पिछले 17 सालों में कृषि उत्पाद डैच से भी नीचे बिकने पर किसान को 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। किसान घाटे की खेती कर रहा है, उसके कारण वह कर्ज के चक्र से नही निकल पा रहा है। 1972–73 में एक किलो गेहूं से एक लिटर डिजल मिल जाता था। आज 4 किलो गेहूं से एक लिटर डीजल मिलता है। किसान ने देश को अपने विवेक तथा सरकार के जरा से प्रोत्साहन से अन्न संकट से निकला। किसान कृषि विविधीकरण करने में सक्षम है, उसे फिर अर्थिक सहायता तथा थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिये। सरकार के दिल में किसान और गांव होने चाहिये न कि कारपोरेट जगत। सरकार ने कारपोरेट के दबाव में देसी कृषि बीज को गायब करके राष्ट्रीय अमूल्य सम्पदा नष्ट कर दी। हम फिर इस प्रकार का षड़यंत्र नहीं होने देगे। भूख को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे यानी फसल और नस्ल की लड़ाई – फार्मबिल वापसी फिर घर वापसी। किसान पर बन्दूक का पहरा देश के हित में नहीं है। किसान करूणा का पात्र है न कि असवेदंनशीलता का पात्र। देश की आत्मानिर्भरता का रास्ता खेल–खलियान से जाता है न कि कारपोरेट के हैलीकाप्टर से।"

आगे राकेश टिकैत सचेत है कि "किसान आन्दोलन तीन कानूनों व एम.एस.पी तक सीमित नहीं है। देश के समिति संसाधनों का सदुपयोग होना चाहियें। वे प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि वे गैस सब्सीडी छोड़ने के लिए उपभोगता से अनुरोध कर रहें हैं। उन्हें सांसदों से अनेक प्रकार की पेन्शन छोड़ने का अनुरोध भी करना चाहियें। संसद की कान्टीन में पांचतारा होटल के लंच की कीमत 40–50 रुपये में मिलने वाली थाली की सब्सीडी भी छुडवानी चाहियें। गांधी की भांति हमारे रहनुमाओं को भी सादा जीवन व्यतीत करने की आदत डालनी चाहियें। कृषि सुधार की प्रक्रिया जो

स्वेडीन से अमेरिका होती हुई वाहयशक्तियों के दबाव भारत में किसानों पर लादी जा रही है वह घातक हैं। किसान आन्दोलन पवित्र तो है ही उसके वाहक किसान सवोंच्च स्तर के देश भक्त व देव आत्माएं हैं। वे स्वदेशी प्रक्रिया से देश को पुनः सोने की चिड़ियां बना देगे। उन्हें प्रताड़ित व शोषित न किया जाये। कारपोरेट के हवाले उन्हें करना हमारी संस्कृति के विपरित है।"

अयोध्या में राममन्दिर निर्माणधीन है, अब रामराज्य की प्रतीक्षा है। राम अपने राज्य में मानव व पशु दोनों को द्वार पर आने के बाद स्वयं वहां जाकर उनको सुनते थे। पवित्र, किसान आत्माएं दिल्ली द्वार पर देश के प्रशासक से अपनी पीड़ा का निदान करने हेतू खड़ी हैं– पर उन्हें कोई सुनने नहीं आता। किसानत्रासदी तथा राकेश टिकैत के समर्थन में जगह–जगह पंजाब से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र तक महापंचायत आयोजित की जा रही हैं। किसान राजनीतिक पेचीदगी से दूर है और किसान आन्दोलन सदैव अपने बलबूते पर चले हैं। चौ० महेन्द्र सिंह टिकैत ने समझा लिया कि किसान संघर्ष लम्बा चलेगा, अब किसान संघर्ष का संचालन उनके सुपुत्र राकेश टिकैत के कंधों पर है। किसान को खुशहाली के लिए कितना इन्तजार करना पड़ेगा यह हमारे रहनुमाओं की सोच पर निर्भर है। 'इंडिया बनाम भारत' सोच में महाराष्ट्र किसान नेता शरदजोशी आरम्भ में काफी सक्रिय रहे। बाद में वे बाबा महेन्द्र सिंह को किसान हितों में अवरोधक बन गये एवं अपने स्वार्थ के लिए स्वयं रायसीनहिल नई दिल्ली के कृषिभवन में कुर्सी पर जा बैठे। ऐसी हरकते राकेश टिकैत के साथ न होने के लिये सचेत रहना पड़ेगा।

डिजिटल मीडिया की कसी नकेल

– प्रमोद जोशी

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म हमेशा निरंकुश–निर्द्वंद नहीं रह सकते थे। जिस तरह उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में प्रिंट मीडिया के नियमन ने शक्ल ली, उसी तरह नब्बे के दशक में आकाश मीडिया के नियमन की शुरुआत हुई। पहले उसने केबल के रास्ते आकाश मार्ग से प्रवेश किया, फिर उसका नियमन हुआ, उसी तरह नए डिजिटल माध्यमों के विनियमन की जरूरत होगी। इनकी अंतर्विरोधी भूमिका पर भारत में ही नहीं दुनियाभर में चर्चा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ओटीटी प्लेटफॉर्मों की सामग्री का नियमन होता है और उल्लंघन होने पर सजा देने की व्यवस्था भी है, पर इस विनियमन को युक्तिसंगत भी होना चाहिए। इस मामले में विवेकशीलता नहीं बरती गई, तो लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति का गला घुट सकता है।

पिछले गुरुवार को सरकार ने जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा–निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 जारी किए हैं, उन्हें आना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस आशय के निर्देश दिए थे और हालात खुद कह रहे हैं कि कुछ करना चाहिए। हाल में अमेरिकी संसद और लालकिले पर हुए हमलों से इसकी जरूरत और पुख्ता हुई है। मर्यादा रेखाएं इंटरनेट और डिजिटल मीडिया ने सामाजिक–शक्तियों और राजशक्ति के बीच भी मर्यादा रेखा खींचने की जरूरत को रेखांकित किया है। सामान्यतः माना जाता है कि सार्वजनिक हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की है, पर जैसे–जैसे तकनीक का दायरा हमें राज्य की राजनीतिक सीमाओं से भौगोलिक रूप से बाहर ले जा रहा है, नए सवाल उठ रहे हैं। नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर तक होती है, पर भविष्य में अंतरराष्ट्रीय नियमन की जरूरत भी होगी। बेशक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने नागरिकों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पर इनका दुरुपयोग भी होता है। सामुदायिक विद्वेष बनाने और बढ़ाने दोनों कार्यों में सोशल मीडिया की भूमिका है। दूसरी तरफ इसकी नकारात्मक भूमिका को रोकने के सारे औजार राज्य के हाथों में सौंपने के खतरे हैं। उनका बड़ी तकनीकी कम्पनियों के हाथ में रहना भी खतरनाक है। अंततः यह सामाजिक विकास से जुड़ा मसला है। यकीनन किसी समय पर जाकर समाज आत्म–नियमन के सांचे और ढांचे को आत्मार्पित करने की स्थिति में जरूर होगा, पर आज की स्थिति में सामाजिक व्यवस्था राष्ट्र–राज्य के मार्फत ही संचालित हो रही है। इससे जुड़े नियम बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है, जो प्रकारांतर से सरकार है। सन 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने श्एयरवेव्सश की स्वतंत्रता और उसके नियमन से जुड़े फैसले में यह जिम्मेदारी सरकार को सौंपी थी।

बढ़ते ट्रांस खतरे नागरिक के जानकारी पाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों को पंख लगाने वाली तकनीक ने उसकी उड़ान को अंतरराष्ट्रीय जरूर बना दिया है, पर उसकी आड़ में बहुत से खतरे राष्ट्रीय सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। सोचना उनके बारे में भी होगा। श्फेक–न्यूजश ने सूचना और जानकारी की परिभाषा को बदल दिया है। बड़ी टेक–कंपनियां नागरिकों और राज्य–व्यवस्था के बीच आ गई हैं। जानकारी पाने, विचार व्यक्त करने और लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी के अधिकारों पर इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ेगा। इस टेक्नो–लोकतंत्र के दो पहलू हैं। एक, सोशल मीडिया और दूसरे

हम आजाद तभी पाते हैं, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। – रवीन्द्रनाथ टैगोर

ओटीटी प्लेटफॉर्म। दोनों ने आम आदमी को मजबूत किया है, लेकिन उनके गैर–जिम्मेदाराना इस्तेमाल की शिकायतें भी हैं। नए नियमों के तीन उद्देश्य हैं। एक, शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना। प्लेटफॉर्मों को इस काम के लिए अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जो एक समयावधि में शिकायत का निवारण करेंगे। इसी तरह सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए के लिए अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। तीसरे, यह व्यवस्था प्रिंट और टीवी मीडिया के लिए पहले से बने नियमों के अनुरूप हो।

हैंडल की पहचान नए नियम कहते हैं कि किसी भी सूचना को सबसे पहले सोशल मीडिया में लाने वाले की पहचान करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की है। यह सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट न बनाए जाए, कंपनियों से अपेक्षा होगी कि वे वैरीफिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य बनाएं। कोई पोस्ट किसने किया है, इसकी जानकारी कोर्ट के आदेश या सरकार के पूछने पर देनी होगी। भारत के बाहर से हुआ तो भारत में किसने शुरू किया। कंपनियां कहती हैं कि ऐसा करने के लिए एनक्रिप्शन के सुरक्षा–चक्र को तोड़ना होगा, जिससे प्राइवेसी भंग होगी। इस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम एनक्रिप्शन तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस यह पूछ रहे हैं कि इसे शुरू किसने किया।

बहुत से हैंडल अपनी पहचान नहीं बताते। लोकतंत्र में गुमनामी भी अपनी बात को कहने का एक औजार है, पर गुमनामी के खतरे भी हैं। सामाजिक–सुरक्षा के लिए गुमनामी खतरनाक भी हो सकती है और पहचान बताने की अनिवार्यता व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करती है। आत्म–नियमन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म (ओटीटी) कंटेंट की सेंसरशिप का विचार नहीं है, लेकिन कंटेंट पर प्लेटफॉर्म्स को आत्म–नियमन करना होगा। सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तीन स्तर की नियमन प्रक्रिया तय करनी होगी– पहले सेल्फ रेग्यूलेट करना होगा। दूसरे स्तर पर सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी कंटेंट का नियमन करेगी। शिकायतें सुनने के लिए एक संस्था बनानी होगी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर जज करेंगे। तीसरे स्तर पर ओवर साइट मिकैनिज्म होगा। उन्हें अपनी सामग्री का दर्शक की उम्र के हिसाब से पाँच श्रेणियों में वर्गीकरण करना होगा। इन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होंगी। सरकार चाहती है कि मीडिया आत्म–नियमन करे। यह आत्म–नियमन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले से कर रहा है। डिजिटल तकनीक के विस्तार को देखते हुए उसमें अनुपालन और मध्यस्थ अधिकारियों की भूमिका बढ़ेगी, जिससे जटिलताएं भी बढ़ेंगी। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार एबसल्यूट नहीं हैं। अनुच्छेद 19 (2) के तहत उनपर युक्तियुक्त बंदिशें हैं। सवाल है कि बंदिशों का नियमन कौन करेगा? सरकार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? नियमन का दायरा हाल में देश कुछ ट्विटर हैंडलों को लेकर यह सवाल खड़ा हुआ था। सरकार का कहना था कि कुछ हैंडल मर्यादा रेखा पार कर रहे हैं। ट्विटर ने शुरू में सरकार की बात नहीं मानी, पर दबाव पड़ने पर मानीं। इन नियमनों के समय को देखते हुए लगता है कि इसका ट्रिगर प्वाइंट यही है, पर नियमन सोशल मीडिया को लेकर ही नहीं हैं। मनोरंजन ओटीटी मीडिया का केवल एक पहलू है। इसका दायरा बड़ा है।

हरियाणा बजट पर टिप्पणी , घोषणाओं का क्रियान्वयन चुनौती

– शंभू भद्रा

बजट किसी भी सरकार की हो, उसमें हमेशा इरादे नेक होते हैं, घोषणाओं से जनता को लुभाने की कोशिश होती है। असली परीक्षा तो घोषणाओं के क्रियान्वयन में होती है। हरियाणा की भाजपा–जजपा गठबंधन की सरकार ने भी अपने नए बजट में यही कोशिश की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के रूप में नई छाप छोड़ने की कोशिश की है। अंत्योदय विजन के साथ हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की बुनियाद इस बार के बजट में दिख रही है। कोरोना से पस्त राज्य की सरकार के लिए जनता में सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगाना बड़ी चुनौती थी, वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में मनोहर सरकार इस चुनौती का सामना करती दिख रही है। सरकार ने गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार और पंचायतों के राजस्व सृजन पर ध्यान दिया है तो शहरों की दशा में भी परिवर्तन लाने का संकल्प दिखाया है। बजट में बिजली पर मामूली सेस को छोड़कर नया कर नहीं लगा कर प्रदेशवासियों को राहत दी है। देखने वाली बात यह है कि सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे पार पाने की दिशा में कितना प्रयास किया गया है।

कोविड काल में वर्ष 2020 के दौरान सरकार को 12 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद अब वित्त वर्ष 2021–22 के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 फीसदी अधिक राशि के बजट का प्रस्ताव किया है। यह साहसी कदम है। पिछला बजट 1,42,378 करोड़ रुपये का था, इस बार का बजट 1,55,645 करोड़ रुपये का

है। सरकार को नए वित्त वर्ष में 3.87 फीसदी राजकोषीय घाटा का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा 2.90 फीसदी रहा था। करीब डेढ़ लाख करोड़ के बजटीय प्रावधान वाले राज्य के लिए 3.87 फीसदी राजकोषीय घाटा का अनुमान बहुत ज्यादा है। इतने बड़े घाटे के साथ विकास योजनाओं को आगे ले जाना बड़ी चुनौती होगी। बजट में आत्मनिर्भर हरियाणा का संकल्प है। बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि, 9वीं से 12वीं तक मुत शिक्षा, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाना, 20 हजार सस्ते मकान, किसानों के लिए दो नई योजनाएं, पंचकूला व हिसार को स्मार्ट सिटी बनाने, एक लाख निर्धनतम परिवारों के लिए अंत्योदय उत्थान अभियान, पुलिस पर ध्यान जैसी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। ग्राम दर्शन योजना से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है।

आंकड़ों में देखा जाय तो हरियाणा समृद्ध राज्यों में शुमार है। प्रति व्यक्ति आय में भी राज्य बहुत आगे है, लेकिन इसी के साथ राज्य में बेरोजगारी दर भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। गत दिसंबर के आंकड़े के मुताबिक हरियाणा में 32 फीसदी तो कुछेक अलग एजेंसियों के मुताबिक 28 फीसदी बेरोजगारी दर है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से बेरोजगारी दर करीब 26 फीसदी है। सही आंकड़े जो भी हो, लेकिन सूबे में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। सरकारी क्षेत्र में दिनोंदिन नौकरियां घटती जा रही हैं, ऐसे में बेरोजगार युवाओं के निए नए रोजागार का सृजन करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। मनोहर सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण का दांव अवश्य खेला है, लेकिन निजी क्षेत्र इस पर कितना अमल करेंगे, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस फैसले पर फिक्की, सीआईआई समेत अन्य उद्योग संगठनों ने नाखुशी जताई है। इस हिसाब से मनोहर सरकार के इस बजट में रोजगार सृजन को लेकर व्यापक रोडमैप दिखना चाहिए था। पर ऐसा नहीं है।

मनोहर सरकार ने कोविड के साये वाले अपने इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, .षि व संबद्ध क्षेत्र, सिंचाई, इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, रेल व एयरपोर्ट), सामाजिक कल्याण, पुलिस प्रशासन, सैन्य, पेयजल, ग्रामीण व शहरी विकास, बिजली आदि पर खास ध्यान दिया है। इन सभी क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है। यह स्वागत योग्य है, पर चुनौतियां इन आवंटनों को योजनाओं के रूप में जमीन पर उतारने की है। एसवाईएल पर 100 करोड़ के आवंटन की घोषणा हर बजट में हो रही है, पर इस दिशा में कोई प्रगति नहीं है। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार नहीं होते। कोविड काल में अस्पतालों में संसाधनों की कमी की पोल खुली। जबकि सरकार पिछले कई बजट से हर जिला में मेडिकल कालेज खोलने, सिविल अस्पतालों में बेड बढ़ाने, जांच उपकरण, वेंटिलेटर आदि को लेकर घोषणाएं करती रही हैं, लेकिन कोविड काल में सबने देखा कि सरकारी अस्पताल किस तरह खस्ता स्थिति में है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का नतीजा है कि मरीजों का बोझ चंडीगढ़ व रोहतक के पीजीआई पर है। इस बार मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7731 करोड़ के बजट का आवंटन किया है, लेकिन कोविड के बाद की स्थिति को देखते हुए बजटीय आवंटन कम है। इसे 15 हजार करोड़ रुपये तक किया जा सकता था। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार सृजन की भी अपार क्षमता है और राजस्व सृजन की भी। सरकार को स्वास्थ्य को रियायत सेवा बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मुत बस गरीबों तक सीमित रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य सेवा को आत्मनिर्भर बनाना आसान होगा।

बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि, 9वीं से 12वीं तक मुत शिक्षा, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाना, 20 हजार सस्ते मकान, किसानों के लिए दो नई योजनाएं, एक लाख निर्धनतम परिवारों के लिए अंत्योदय उत्थान अभियान, पुलिस पर ध्यान जैसी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। ग्राम दर्शन योजना से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। बजटीय आवंटन सराहनीय है, लेकिन योजनाओं के लिए रोडमैप का अभाव है। सरकार अगर इस ओर ध्यान दे तो बजट से तेजी से ग्रोथ होगा। बजट घोषणाओं को अमलीजामा पहनना सरकार की असल चुनौती होगी। किसी भी सरकार की हो, उसमें हमेशा इरादे नेक होते हैं, घोषणाओं से जनता को लुभाने की कोशिश होती है। असली परीक्षा तो घोषणाओं के क्रियान्वयन में होती है। हरियाणा की भाजपा–जजपा गठबंधन की सरकार ने भी अपने नए बजट में यही कोशिश की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के रूप में नई छाप छोड़ने की कोशिश की है। अंत्योदय विजन के साथ हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की बुनियाद इस बार के बजट में दिख रही है। कोरोना से पस्त राज्य की सरकार के लिए जनता में सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगाना बड़ी चुनौती थी, वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में मनोहर सरकार इस चुनौती का सामना करती दिख रही है। सरकार ने गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार और पंचायतों के राजस्व सृजन पर ध्यान दिया है तो शहरों की दशा में भी परिवर्तन लाने का संकल्प दिखाया है। बजट में बिजली पर मामूली सेस को छोड़कर नया कर नहीं लगा कर प्रदेशवासियों को राहत दी है। देखने वाली बात यह है कि सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे पार पाने की दिशा में कितना प्रयास किया गया है। कोविड काल में वर्ष 2020 के दौरान सरकार को 12 हजार करोड़ के राजस्व का

धैर्य रखना मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। – ससो

नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद अब वित्त वर्ष 2021–22 के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 फीसदी अधिक राशि के बजट का प्रस्ताव किया है। यह साहसी कदम है। पिछला बजट 1,42,378 करोड़ रुपये का था, इस बार का बजट 1,55,645 करोड़ रुपये का है। सरकार को नए वित्त वर्ष में 3. 87 फीसदी राजकोषीय घाटा का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा 2.90 फीसदी रहा था। करीब डेढ़ लाख करोड़ के बजटीय प्रावधान वाले राज्य के लिए 3.87 फीसदी राजकोषीय घाटा का अनुमान बहुत ज्यादा है। इतने बड़े घाटे के साथ विकास योजनाओं को आगे ले जाना बड़ी चुनौती होगी। बजट में आत्मनिर्भर हरियाणा का संकल्प है। बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि, 9वीं से 12वीं तक मुत शिक्षा, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाना, 20 हजार सस्ते मकान, किसानों के लिए दो नई योजनाएं, पंचकूला व हिसार को स्मार्ट सिटी बनाने, एक लाख निर्धनतम परिवारों के लिए अंत्योदय उत्थान अभियान, पुलिस पर ध्यान जैसी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। ग्राम दर्शन योजना से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। आंकड़ों में देखा जाय तो हरियाणा समृद्ध राज्यों में शुमार है। प्रति व्यक्ति आय में भी राज्य बहुत आगे है, लेकिन इसी के साथ राज्य में बेरोजगारी दर भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। गत दिसंबर के आंकड़े के मुताबिक हरियाणा में 32 फीसदी तो कुछेक अलग एजेंसियों के मुताबिक 28 फीसदी बेरोजगारी दर है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से बेरोजगारी दर करीब 26 फीसदी है। सही आंकड़े जो भी हो, लेकिन सूबे में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। सरकारी क्षेत्र में दिनोंदिन नौकरियां घटती जा रही हैं, ऐसे में बेरोजगार युवाओं के निए नए रोजागार का सृजन करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। मनोहर सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण का दांव अवश्य खेला है, लेकिन निजी क्षेत्र इस पर कितना अमल करेंगे, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस फैसले पर फिक्की, सीआईआई समेत अन्य उद्योग संगठनों ने नाखुशी जताई है। इस हिसाब से मनोहर सरकार के इस बजट में रोजगार सृजन को लेकर व्यापक रोडमैप दिखना चाहिए था। पर ऐसा नहीं है)

अपने इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, .षि व संबद्ध क्षेत्र, सिंचाई, इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, रेल व एयरपोर्ट), सामाजिक कल्याण, पुलिस प्रशासन, सैन्य, पेयजल, ग्रामीण व शहरी विकास, बिजली आदि पर खास ध्यान दिया है। इन सभी क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है। यह स्वागत योग्य है, पर चुनौतियां इन आवंटनों को योजनाओं के रूप में जमीन पर उतारने की है। एसवाईएल पर 100 करोड़ के आवंटन की घोषणा हर बजट में हो रही है, पर इस दिशा में कोई प्रगति नहीं है। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार नहीं होते। कोविड काल में अस्पतालों में संसाधनों की कमी की पोल खुली। जबकि सरकार पिछले कई बजट से हर जिला में मेडिकल कालेज खोलने, सिविल अस्पतालों में बेड बढ़ाने, जांच उपकरण, वेंटिलेटर आदि को लेकर घोषणाएं करती रही हैं, लेकिन कोविड काल में सबने देखा कि सरकारी अस्पताल किस तरह खस्ता स्थिति में है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का नतीजा है कि मरीजों का बोझ चंडीगढ़ व रोहतक के पीजीआई पर है। इस बार मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7731 करोड़ के बजट का आवंटन किया है, लेकिन कोविड के बाद की स्थिति को देखते हुए बजटीय आवंटन कम है। इसे 15 हजार करोड़ रुपये तक किया जा सकता था। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार सृजन की भी अपार क्षमता है और राजस्व सृजन की भी। सरकार को स्वास्थ्य को रियायत सेवा बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मुत बस गरीबों तक सीमित रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य सेवा को आत्मनिर्भर बनाना आसान होगा, शिक्षा क्षेत्र में चाहे उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक व प्राथमिक, सभी मेनपावर, बेसिक सुविधाओं से जूझ रहे हैं। इस बार अच्छी बात है कि सरकार ने 18 हजार करोड़ से अधिक का आवंटन शिक्षा क्षेत्र के लिए किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा वेतन पर जाएगा, फिर भी सरकार की मंशा सुधार की लग रही है। रोजगार सृजन के लिए जरूरी है कि शिक्षा के पूरे पैटर्न को बदला जाय। अक्षर के ज्ञान से बाहर निकल कर स्किल एजुकेशन को पांचवीं के बाद से शिक्षा का केंद्र बनाना चाहिए। आज डिजिटल सेक्टर में स्किल्ड वर्कफोर्स की भारी मांग है, इसलिए हमें अपने माध्यमिक एजुकेशन को पूरी तरह स्किल्ड बेस्ड बनाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थाउट, केटरिंग, स्मार्ट प्लंबिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर आदि को माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। आवंटन बढ़ने का फायदा शिक्षा सुधार में दिखना चाहिए। किसान आंदोलन के साये में आए बजट में सरकार ने पिछले साल से 21 फीसदी अधिक राशि .षि क्षेत्र के लिए दी गई है। यह अच्छा है पर सरकार .षि सेक्टर में सहकारी खेती, राजमार्ग के किनारे एग्री मार्ट, शीत भंडारण, परंपरागत खेती में बदलाव जैसी घोषणाएं बजट में कर सकती थी। इससे सही मायने में .षि क्षेत्र की कायापलट होती। इस क्षेत्र में रोजगार की बड़ी क्षमता है। बजटीय आवंटन सराहनीय है, लेकिन योजनाओं के लिए रोडमैप का अभाव है। सरकार अगर इस ओर ध्यान दे तो बजट से तेजी से ग्रोथ होगा। बजट घोषणाओं को अमलीजामा पहनना सरकार की असल चुनौती होगी।

जिसके पास विद्या रूपी नेत्र नहीं है, वह अंधे के समान है। – अज्ञात

वज्र से बढ़ेगी तोपखाने की ताकत

– डा. एल.एस. यादव

भारतीय सेना के तोपखाना बेड़े में 18 फरवरी को उसकी 100वीं तोप के–9 वज्र टी शामिल हो गई है। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवने ने सूरत में इसे हरी झंडी दिखाकर इसे भारतीय सेना में शामिल किया। भारतीय सेना को मिलने वाली इन तोपों का निर्माण भारत में ही एलएंड टी कंपनी द्वारा किया गया है। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस तोप को गुजरात के हजीरा प्लांट में तैयार किया गया है। के–9 वज्र टी तोप एक स्वचालित तोप है। इस श्रेणी की तीन तोपों को लेह पहुंचाया जा चुका है। अब उन्हें परीक्षण के लिए अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। वहां यह देखा जाएगा कि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग शत्रु सेना के खिलाफ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है या नहीं।

इन तोपों की ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना पर्वतीय अभियानों के लिए इन स्वचालित तोपों की दो या तीन अतिरिक्त रेजिमेंट बनाने के लिए नई खरीद का आर्डर दे सकती है। लार्सन एंड टुब्रो(एलएंडटी) ने सेना को 100 के–9 वज्र टी स्वचालित तोपों की आपूर्ति की है। इनको पिछले दो वर्षों में विभिन्न रेजिमेंटों में तैनात किया गया है। उल्लेखनीय है कि के–9 वज्र टी तोप दक्षिण अफ्रीका की के–9 थंडर तोप का स्वदेशी संस्करण है। इस स्वचालित तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर की दूरी तक की है। यह तोप जीरो रेडियस पर घूमकर चारों तरफ हमला करती है। 155 एमएम 52 कैलिबर की यह तोप 50 टन वजन वाली है। यह 47 किलोग्राम का गोला फेंकने की क्षमता रखती है। मात्र 15 सेकेंड में शत्रु पर यह तीन गोले गिराने में सक्षम है। इसके द्वारा फेंका गया गोला 928 मीटर प्रति सेकेंड यानी एक मिनट में 55680 मीटर की दूरी तय करता है। ऐसी तोपें चीन की सीमा या पाकिस्तान की सीमा पर जब तैनात रहेंगी तो दुश्मन का चिन्तित रहना स्वाभाविक है। इनकी तैनाती से पर्वतीय युद्ध क्षेत्र में भारत का पलड़ा भारी हो गया है।

अब तोपों के प्रदर्शन के आधार पर भारतीय सेना दो या तीन अतिरिक्त रेजीमेंट के लिए इन तोपों की खरीद का आर्डर दे सकती है। ज्ञातव्य है कि वर्श 1986 में भारतीय सेना में शामिल की गई होवित्जर तोपों ने 1999 के कारगिल संघर्ष के समय पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए ऐसी तोपों की सेना को विशेष आवश्यकता है जो लद्दाख जैसे पर्वतीय इलाके में युद्ध के समय विजयी भूमिका निभा सकें। भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में दुश्मन को मुहंतोड़ जवाब देने के लिए पिछले वर्श एम–777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें तैनात की थीं जिनकी भूमिका ठीक रही थी। भारतीय सेना की यौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) इस समय मेक इन इंडिया योजना के तहत एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम होवित्जर तैयार करने का कार्य कर रहा है। अगले साल इन तोपों को भी भारतीय सेना के तोपखाना बेड़े में शामिल किया जा सकता है। डीआरडीओ ऐसी लगभग 200 तोपों के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। अब नई आधुनिक तोपों के आ जाने से लद्दाख में सेना की आर्टिलरी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।

इससे पहले 20 दिसम्बर 2020 को डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी होवित्जर तोप एटीएजीएस का परीक्षण ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में किया गया था जो कि सफल रहा था। डीआरडीओ के एटीएजीएस प्रोजेक्ट डायरेक्टर शैलेन्द्र गाडे के मुताबिक यह दुनिया की सबसे बेहतर किस्म की तोप है। अभी तक किसी दूसरे देश ने ऐसी तोप विकसित नहीं की है। यह एडवांस्ड टावर आर्टिलरी गन 48 किलोमीटर की दूरी से ही अत्यन्त सटीक तरीके से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। अगर इस तोप के ऑपरेशनल पैरामीटर की बात की जाए तो यह 25 किलोमीटर प्रति घण्टा मूव कर सकती है। आने वाले दिनों में भारत इनकी तैनाती चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कर सकता है। गत वर्ष 20 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश स्थित वाहन निर्माणी जबलपुर ने 130 मिलीमीटर पुरानी सारंग तोपों को अपग्रेड करके सेना को सौंप दिया था। अब उन्नत सारंग तोप में 28 के बजाय 38 किलोमीटर की अचूक मारक क्षमता है। इसकी विध्वंसक क्षमता में भी काफी वृद्धि हो गई है। यह अत्याधुनिक तोप वजन में भी बेहद हल्की है। इसका लाजवाब प्रदर्शन देखकर सैन्य अधिकारी 200 और पुरानी सारंग तोपों के अपग्रेड करने का आदेश दे दिया है। विदित हो कि भारतीय सेना को इस समय 1580 टोड तोपों के अलावा 150 एटैग्स एवं 114 धनुष तोपों की विशेष रूप से जरूरत है। इस तरह सेना को कुल 1800 तोपों की आवश्यकता है। भारतीय सेना लगभग 1600 तोपें खरीदना चाहती है। इसके लिए इजरायल से 400 एथोस तोपें तुरन्त मांगने का विकल्प भी रखा गया है। इसके अलावा फ्रांस से नेक्सटर तोपें भी खरीदी जा सकती हैं। इन नई तोपों के मिलने से सेना की यह कमी आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी और भारतीय तोपखाना काफी ताकतवर हो जाएगा।

खाप पंचायतें-तब और अब

– जयवंती श्योकंद

समाज व समाजिक परम्पराओं का गठन इनसान की भलाई के लिए हुआ। न्याय, नैतिक मूल्यों व समाज रक्षा के प्रतिनिधि खाप पंचायतों का वजूद प्राचीन काल से आ रहा है। पंच का शाब्दिक अर्थ ही न्यायनिष्ठ व कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति है तो पंचों द्वारा पंचायत भी उसी न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखने वाली संस्था है। ये पंच समाज के ऐसेव्यक्ति हुआ करते थे जिन पर पूरे समाज को भरोसा था। समाज गणों में बंटा हुआ था और गण अथवा खाप पंचायतों लोकतांत्रिक तरीके समस्याओं को आपसी विचार–विमर्श के माध्यम से सुलझाने की व्यवस्था थी। इससे ऊपर इनका काम समाज उत्थान, सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करके समाज का मार्ग–दर्शन करना था।

प्रमाण मिलते हैं कि हर्षवर्धन से लेकर अलाऊद्दीन खिलजी मलिक काफूर, मौलाना अल्ताक हुसैन अली, सिंकदर लोधी, शेरशाह सूरी, बाबर, राणा कुम्भा, गुरु रामदास, राणा सांगा, जैन साधु समाज, शेख सलीम चिश्ती, शेख फरीद, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी इत्यादि संतों, राजाओं, शासकों, विचारकों ने खाप पंचायतों के वजूद को मानकर उनके कार्यों की प्रशंसा भी की थी और इन्हीं में कुछों ने उन्हें समाजोपयोगी नेक काम करने के उपदेश भी दिए थे। उपदेश अमूमन धार्मिक मेलों के दौरान (हरिद्वार आदि जैसे) एकत्रित हुए स्त्री–पुरुषों को दिए जाते थे और उन्हीं के माध्यम से बाकी आबादी को।

इतिहास गवाह है कि जजिया टैक्स का विरोध सबसे पहले सन 1668 में आगरा और मेरठ की खाप पंचायतों ने किया था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को निरन्तर हजारों मन दूध, घी, गुड़, सामग्री आदि देकर खाप पंचायतों ने क्रांतिकारियों के मनोबल को सुदृढ़ किया। इन्ही पचायतों ने दिल्ली सम्राट बहादुरशाह जफर जिसका राज्य उस समय केवल लाल किले तक ही (सल्तनत शाह आलम, आज दिल्ली ता पालम) सीमित था, को तमाम हिन्दुस्तान का बादशाह मानकर घोषणा की थीः– "गैर मुल्क की हुकूमत को हटाकर बहादुरशाह जफर को बादशाह माना जाए। राजा और नवाब, पंडित और मौलवी, फकीर और साधुसंत मिलकर मुल्क की आजादी को हल कर लें और खान बहादुर बख्ता खान को तमाम हिन्दुस्तान की फौजों का सबसे बड़ा सिपहसालार बना कर अपने मुल्क से गैर मुल्की फिरंगियों को हटाकर मुल्क को गुलामी के फंदे से निजात दें।" खाप पंचायतों के इस आग्रह के बावजूद सम्राट बहादुरशाह जफर ने दिल्ली कमान बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को सौंपी थी। सन 1857 के संग्राम में शहीद हुए वीरों के परिवारों के पालन–पोषण व बच्चों की शिक्षा का प्रबंध खाप पंचायतों ने ही किया था।

प्राचीन विशाल हरियाणा की सर्वखाप द्वारा चलाया गया अभियान दक्षिण भारतीय विजय साम्राज्य की सेना में भी बल भरने का काम कर रहा था। ईरान के लेखक हसन अब्बास ने लिखा, "भारत उत्तर भारत में हरियाणा जन्नत का मुकाम है।" खाप पंचायतों में भारत के सभी धर्मों व सम्प्रदायों के लोग, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी हिन्दु, मुसलमान सभी शामिल होते थे। सभी जातियों में सबका बराबर भाई–चारा था। योग्यता अनुसार सम्मान किया जाता था। गुणवान पण्डित की सबसे अधिक मान्यता थी। क्षत्रिय वीर समूह में हिन्दु–मुस्लिम जाट, अहीर, गुजर, राजपूत सैनी,रोड़ इत्यादि के इलावा गडरिए, जोगी, नाई, कुम्हार, लोहार, भंगी, वैश्य, बाह्मण, बढ़ई, तेली, कहार, गोसाई, मनियार, मिरासी इत्यादि सभी जातियों ने मिलकर देश की रक्षा की थी। खाप पंचायतों ने सदा देश भक्ति को धर्म और जाति से ऊंचा समझा।

1857 का संग्राम हिन्दु–मुस्लिम सभी ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। धर्मों और जातियों की एकता का एक बेजोड़ नमूना जिसे अंग्रेजों ने अपने लिए खतरे की घण्टी माना। 'फूट डालो और शासन करो' के कुटिल नियम के आधार पर खाप पंचायतों में आपसी एकता और समाज उत्थान के लिए कही जाने वाली बातें अंग्रेजी को सहन नहीं हुई और जैसे–जैसे भारत में उनके पांव पुनः जमते गए, इन प्राचीन संगठनों को धक्का लगा और इनकी वार्षिक मीटिंगों पर पाबंदी लगा दी गई और यदि किसी वर्ग विशेष ने किसी मीटिंग आदि करने की हिम्मत की तो उन पर सरकारी तत्र का अंकुश रहता था। ऐसा 7 मार्च सन 1911 एक शताब्दी पहले हुई मीटिंग की प्रोसीडिंग से जाहिर होता है। नमूना देखिएः–

"तारीख 7 मार्च 1911 मुताबिक फाल्गुण सुदी 7 सम्वत् 1968 मंगलवार पंचायत कौम जाटान इलाका हरियाणा जिला रोहतक, हिसार, गुड़गांव, दिल्ली करनाल व रियासत जींद ने बमुकाम बरौणा, जिला रोहतक इकट्ठे होकर फजूलखर्ची व बदरसूनात के मुताल्लिक व इत्तफाक राय व बमौजूदगी जनाब सुपरिटेन्डेंट साहब बहादुर पुलिस जिला रोहतक व इंसपेक्टर साहिब व तहसीलदार साहब व डिप्टी इंसपैक्टर साहिबान पुलिस जिला रोहतक व निजमैम्बो दर्जखुदा इश्तिहार हजा बहाजरी तकरीबन पचास हजार साहबान ब्रादर मुफस्सिला जैल रेजोलीशन पास किए जिनको हम अपनी आदिल गवर्नमेन्ट के अबदी राज्य के जेर साये रहते हुए रियाज देकर कौम की तीक्की का बाइस समझेंगे।"

एक शताब्दी पहले हुई रोहतक के ग्राम बरौणा की इस खाप पंचायत में हरियाणा में तालीम की कमी, मदरसों का निर्माण, औरतों के कल्याण, विवाह रस्मों व अन्य फजूलखर्ची पर पाबंदी लगाने जैसे मुद्दो पर विचार–विमर्श हुआ था। आज भी यह पुराना रिकार्ड मौजूद है। इसके अतिरिक्त भी दहेज विरोधी कानून बनने से पहले व श्री हरबिलास शारदा द्वारा बाल विवाह निषेध बिल प्रस्तुत करने से पहले

हम आजाद तभी पाते हैं, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। –रवीन्द्रनाथ टैगोर

ही खाप पंचायतों ने इन कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले व तुरन्त बाद भी खाप पंचायतों द्वारा पारित प्रस्तावों के कुछ मुद्दे देखिए।

- शादी–ब्याह, सगाई में लेन–देन रस्मो–रिवाज से जो धन बचे वह शिक्षा व समाज सुधार पर लगाया जाए।
- विवाह की उम्र दस वर्ष से ऊपर हो।
- बाल विधावाओं का पुनर्विवाह करो।
- पानी और वाणी को शुद्ध रखो।
- छुआछूत त्यागो, छोटा बड़ा केवल कर्म से मानो।
- देश, धर्म, समाज का सम्मान करो।
- लड़के, लड़कियों को पढ़ाओ, उन्हें योग्य बनाओ।
- देश प्रेम का पाठ पढ़ाओ।
- कन्या कुल का सम्मान करो।

अंग्रेजों के भारत में पांव पसारने से पहले खाप पंचायतें सभी जातियों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करती थी तथा उनमें सभी धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग, बिरादरी, जातियों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहला सम्मेलन 1950 में हुआ जिसमें चौधरी जवान सिंह गुजर प्रधान बने थे। वर्ष 1962–66 के दौरान पंडित जगदेव सिद्धान्ती भी सर्वखाप पंचायत के प्रधान रहे।

मुंशी प्रेमचन्द की कहानी पंच–परमेश्वर की तरह खाप पंचायतों के फैसले नैतिकता के सिद्धान्तों पर आधारित होते थे। पंचों को न्यायव समाज रक्षा का प्रतिनिधि माना जाता था। पंचायत में लोटे में नमक डालना उमदा किसम की कसम थी जो आज न्यायालयों में केस पैरवी में 'जो कहूंगा धर्म से सच कहूंगा' से ज्यादा विश्वसनीय थी। इन पंचायतों में साधन विहीन असहाय व्यक्ति भी न्यायकारी आदिल की छवी देखता था।

अतीत के सामाजिक मुद्दे व समस्याएं खाप पंचायतों व समाज सुधारकों ने पहले उठाए और सरकारों ने बाद में ध्यान दिया। दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज कानून बनने से पहले पंचायतों ने उठाई थी व कुछ हद तक उन्हें लागू भी किया। बाल विवाह के विरुद्ध पहले खाप पंचायतें ही मुखरित हुई थी। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असैम्बली (Imperial Legislative Assembly) में 15 दिसम्बर 1927 को बाल विवाह निषेध बिल प्रस्तुत करते हुए श्री हरबिलास शारदा ने बताया था कि 1921 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर भारत में 612 हिन्दु विधवाएं ऐसी थी जिन्होंने एक साल की आयु भी पूरी न की थी। एक से दो वर्ष की आयु की 498, दो से तीन वर्ष की 1280, अर्थात् 5 वर्ष से कम आयु की 12016 विधवाएं थी। 5 से 10वर्ष की 85580, दस से पंद्रह वर्ष की 233533 अर्थात् 15 वर्ष से कम उम्र की 3,31,793 विधवाएं केवल हिन्दुओं में ही थी। काफी शोर शराबे के बाद शारदा एक्ट 1929 में पास हुआ, लेकिन इससे बहुत पहले ही खाप पंचायतें बाल विवाह के विरुद्ध व विधवा विवाह के समर्थन में पुरजोर आवाज उठा चुकी थी। इतना ही नहीं शादियों में बारातियों की संख्या निश्चित व सीमित करके दान–दहेज की ऐसी मात्रा निश्चित की जिससे हजारों बेटियों के मां– बाप कर्ज की दुःखदायी विरासत से बच गए (पाकिस्तान में आज भी शादियों में फजूलखर्ची पर पाबन्दी है व शादी समारोह में केवल कोई एक आइटम ही खाद्य सामाग्री के तौर पर परोसा जा सकता है।)

विभिन्न राज, शासन सत्ताएं आई और चली गई। खाप पंचायतों का वजूद 21वीं सदी तक विद्यमान है। शायद इनके फैसले व उनका कार्यान्वयन समय की मांग के अनुरूप रहे होंगे और खूबियों की वजह से इनकी हस्ती आज तक नहीं मिटी। लेकिन पिछले लगभग एक दशक से खाप पंचायतों की चर्चा हरियाणा व अन्य भागों में जन–जन तक हुई है। एक समय में सर्वमान्य रही खाप पंचायतों को वर्तमान में विवादों व अवराधारणाओं आदि से बचना चाहिए।

आज समय बदल चुका है। परिधान व परम्पराएं देश, काल, परिस्थिति व परिवेश के अनुसार बदलती रही हैं व बदलनी भी चाहिए। मेरी मां व सास अपने दामणों व सलवार सूटों की वेशभूषा सहित स्वयं के लिए पर्दा प्रथा की समर्थक थी, लेकिन मेरे लिए उनकी विचारधारा बिलकुल बदल चुकी थी। आज का दादा हवाई जहाज में उड़ते पोते को 'मेरे साथ बैलगाड़ी में बैठने को कहेगा तो उपहास ही होगा। 21 वीं सदी ने समाज में बहुत से परिवर्तन देख लिए हैं। प्राचीन परम्पराओं व आधुनिकता में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी परम्पराओं का त्याग तो करना ही पड़ेगा जो समाजोपयोगी नहीं रही। कालिदास मालविकाग्निमित्रम् नाटक में कहते हैं कि पुराणमिति एव न साधु सर्वम। हर पुरानी रीति व वस्तु ही अच्छी नहीं होती। आज ग्रामीण नारी समाज अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, पारिवारिक हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, लिगं भेद इत्यादि अन्य दर्जनों समस्याओं से ग्रस्त है। अगर खाप पंचायतें या इनके प्रतिनिधि, समाज व सरकारें इन समस्याओं के बारे में चिन्तित नहीं तो विडम्बना ही है। कर्मठ, सदाचारी, ईमानदार, कानून के ज्ञाता, नैतिकता के समर्थक, स्वच्छ छवि के लोग यदि समाज का मार्गदर्शन करें तो समाज लाभान्वित भी हो सकता है।

समाज सुधार व सामाजिक चेतना में मीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान है। खाप पंचायतों के फैसलों के पात्र मूर्ख, नादान और अपना कर्त्तव्य छोड़कर पथभ्रष्ट हुए बच्चों को घर से भाग कर शादी करने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाए उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। मीडिया समाज व ऐसे भागे बच्चों को बताए कि शादी की कोई उम्र भी होती है तथा समय भी।अगर बच्चे अपना कैरियर बना कर शादी करें तो बेहतर होगा और कोई भी उनके आड़े नहीं आयेगा। हरियाणा में उच्चधिकारियों की शादी जाति से बाहर हुई है लेकिन कभी कोई फसाद नहीं हुआ।

खाली दिमाग शैतान का घर है। हमसे पहले जमाने में लड़कियां खाली समय में अपने आपको चर्खा कातने, सीने पिरोने, दुबले

अहंकार से तप नष्ट हो जाता है और इधर–उधर कहने से दान निष्फल हो जाता है। –मनु

लत्ते कढ़ाई, कीर्तन भजन सत्संग, कार्तिक स्नान, दरी–गलीचे, स्वेटर बुनाई इत्यादि कार्यों में व्यस्त रखती थी। आज भी पढ़ाई के साथ–साथ घरों में लड़कियों को स्वयं को व्यस्त रखने के अनेकों काम हैं। पढ़ाई और घर के कामों से ध्यान हटाकर घर से भागने के ताने–बाने बुनते रहना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी 15–16–17–18 साल की उम्र स्कूल व कालिज में मेहनत से पढ़कर कैरियर बनाने व अपने व्यक्तित्व का विकास करने की उम्र है। बेरोजगार, लम्पट, आवारा, लफंगे चरित्रहीन लड़कों के साथ छोटी उम्र में घर–स्कूल–कालेज से भागी किसी भी लड़की का जीवन अब तक सुखी नहीं रहा है। घर बसाने के आंकड़े एक प्रतिशत भी नहीं है। ऐसे भागे जोड़े वैसे भी बेहद गैरजिम्मेदार व्यवहार के स्वामी होते हैं जिन्हें मेहनत करके खाने की कोई कला नहीं आती। सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षा गृहों में जब तक मुत की रोटी व रहन–सहन है तो ठीक है अन्यथा नरेगा जैसी स्कीमों का लाभ तो ये बिना भागे भी उठाकर अपना यापन कर सकते थे।

घर से भागी ऐसी लड़कियों के जीवन का अंत दो–तीन साल या इससे भी पहले आत्महत्या से हुआ है। या फिर ऐसी लड़कियां इधर–उधर जिन्दगी के थपेड़े खाकर तलाक लेती हैं और अपनी नादानी व मूर्खता के कारण जीवन भर मां–बाप व अन्य रिश्तेदारों पर बोझ बनी तिरस्कारपूर्ण जीवन जीती हैं। कुछ ऐसे भागे–भगाए जोड़े मजदूरी और मजबूरी का जीवन यापना करते हुए दक्षिण भारत के होटलों पर बर्तन साफ करते देखे–सुने गए हैं। यह भी मालूम हुआ है कि ऐसे भागी हुई कुछ लड़कियां व्यभिचार व वेश्यावृत्ति अपनाकर जीवन निर्वाह करती हैं क्योंकि बुभुक्षितः किम् न करोति पापम्। जीवन की वास्तविकता सपनों की दुनियां से अलग है। इस मूल्यवान जीवन का ऐसा दुःखदायी विनाश कहां का शौर्य है?

घर से भागी ऐसी लड़कियों को पुलिस सुरक्षा में किस किस्म की 'सुरक्षा' मिलती है, यह कोई भुक्तभोगी लड़की ही बता सकती है। अतः लड़कियों को कब कैसे, किसके साथ भागना है– ये ताने बाने छोड़कर अपने आत्मविश्वास आत्मबल, हिम्मत, धैर्य, परिश्रम, दढ़ निश्चय से घर–समाज व प्रान्त–देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए। नई पीढ़ी की सम्यक् सोच ही उसे उत्थान की ओर ले जाएगी। कुछ महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें जो अपने आत्मविश्वास और परिश्रम से कुछ से बहुत कुछ बन गए। ग्रामीण लड़कियों द्वारा घर से भागकर अपने मां–बाप, समाज, परिवार व सारे गांव को उपहास का पात्र बनवा देना बुद्धिमता या चतुराई नहीं, लानत है। दिल के साथ–साथ बुद्धि, धैर्य, दिमाग और आत्मविश्वास का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर क्यों ग्रामीण लड़कियां घरों से भागकर खाप पंचायतों के विमर्श व विवाद का विषय बने? (वैसे खाप पंचायतों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे वर्ग को तालिबानी हुकम की नहीं, बल्कि उनकी रुग्ण भगोड़ी मानसिकता को परामर्श, चेतना व शिक्षा की आवश्यकता है।)

आज का युवावर्ग देश की असली दौलत है। लड़कियां भी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मेहनत, धैर्य,स्वच्छ छवि, अनुसार से उन्नति की ऊंचाइयां छू रही हैं। वैसे सावधानी की ज्यादा जरूरत उसे होती है, ज्यादा नुकसान की आशंका हो। कही ऐसा न हो कि युवावर्ग व विशेषकर बेटियों की ऐसे भागने की बढ़ती प्रवृत्ति देखकर मां–बाप व सारा ग्रामीण समाज भविष्य के सम्भावित विवादों से बचने हेतु फिर से बाल–विवाह करने को मजबूर हो जाए। वैसे भी कन्या भ्रूण हत्या का दोषी बनकर सारा भारत लड़कियों का कबरिस्तान तो पहले ही बन चुका है।

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl 25/5'2" BDS from Mulana (Ambala). Father DSP in Haryana Police. Preferred match Doctor, in Govt. Job, Land lord. Avoid Gotras: Jaglan, Kadyan, Malik. Cont.: 9416116492
- SM4 Jat Girl (DOB 04.12.90) 30/5'2" MCA. Working in MNC Mohali. Avoid Gotras: Gulia, Malhan, Dalal. Cont.: 9780385939
- SM4 Jat Girl (DOB June, 87) 23/5'2" B. Tech. (CSC). Working as Delivery Manager (Software Developer) in Chandigarh based Company with package Rs. 18 lakh PA. Father retired, mother housewife. Avoid Gotras: Jaglan, Gahlan, Kadyan. Cont.: 7837113731
- SM4 Jat Girl 29/5'7" MDS Doctor. Preferred match form Tri-city. Avoid Gotras: Narwal, Mor, Kadyan. Cont.: 8556074464
- SM4 Jat Girl 26/5'4" M. Tech (ECE) Pursuing PhD from Chandigarh. Preferred match form Tri-city. Avoid Gotras: Narwal, Mor, Kadyan. Cont.: 8556074464
- SM4 Divorced Jat Girl (DOB 20.02.85) 36/5'4" B.Sc, BEd, MSc Match. Employed as teacher on contract in Kendriya Vidyalaya. Avoid Gotras: Gill, Rathi, Goyat. Cont.: 9417216868
- SM4 Jat Girl (DOB 25.04.93) 27/5'4" MSc Nursing. Employed in Kailash Nurshing College Chandimandir. Avoid Gotras: Pilania, Malik, Singroha. Cont.: 9896813684
- SM4 Jat Girl (DOB 16.01.95) 26/5'1" B.Sc. (Hons.) Math, MSc Math, B.Ed, CTET (paper-2) qualified. Avoid Gotras: Redhu, Rana, Tanwar. Cont.: 8802421721, 9417840201
- SM4 Jat Girl (DOB 25.01.90) 30/5'8" B.A. MCM Chandigarh, MSW from K. U. Working as Medical Social Welfare Officer, U. T. Chandigarh. Father Govt. Contractor, mother housewife. Avoid Gotras: Jakhar, Sangwan, Dhankhar, Neel. Cont.: 9215349999
- SM4 Jat Girl (DOB 31.10.95) 25/5'3" BDS from P.U. Chandigarh.Pursuing MPH from Kerala.Father school teacher and mother headmistress.Required Army officer, Doctor or Civil Service Officer. Avoid Gotras: Nain, Dimara, Mehla. Cont.: 9416773199, 7404764580
- SM4 Jat Girl (DOB19.10.86) 34/5'5" MSc (Geography), M.Phil, PhD, NET & JRF qualified. Father retired from gazetted post in Haryana Govt. Avoid Gotras: Panghal, Dalal, Sangwan.Cont.: 9646404899
- SM4 Jat Girl (DOB 88) MA (Economics), PhD (Economics), NET & IELTS cleared. Employed in Chandigarh as Assistant Professor on contract basis. Father class-II officer from Haryana Govt. Brother settled in USA. Avoid Gotras:Dahiya, Sehrawat, Jatrana. Cont.: 9988224040

मनुष्य की जिंदगी एक सुंदर पक्षी की भांति है, जो किसी डाल पर बैठा हुआ थोड़ी देर चहचहाता है और फिर उड़ जाता है। –इकबाल

- SM4 Jat Girl (DOB 15.03.89) 31/5'5" Employed in Indian Overseas Bank as P.O. Avoid Gotras:Gawariya, Sangwan, Sunda. Cont.: 9646519210
- SM4 Jat Girl (DOB 09.11.94) 26/5'4" M.Sc Math, BEd from P. U. Avoid Gotras:Kaliraman, Pawar, Jani. Cont.: 9416083928
- SM4 Jat Girl (DOB 11.08.88) 32/5'6" MBA, LLM. Avoid Gotras:Hooda, Phaugat, Jatan. Cont.: 9896871134
- SM4 Jat Boy 25/5'7", B.A. Doing MBA. Working in reputed MNC at Gurgaon. Father in Chandigarh Police, mother housewife. Avoid Gotras: Antil, Dahiya, Dabas. Cont.: 8146081111
- SM4 Jat Boy 27/5'9", B.A. Working as Assistant in Haryana Govt. at Chandigarh. Family settled in Panchkula with own house. Avoid Gotras: Gahlyan, Antil, Sehrawat. Cont.: 8168563692
- SM4 Jat Boy (DOB 09.02. 94)27/5'8", B.A. Serving in Indian Army. Father Rtd. Class-II officer form Haryana Govt. Own house at Nayagaon (Mohali) and Bhiwani. Avoid Gotras: Sheoran, Sangwan, Punia. Cont.: 9988603681, 9988359360
- SM4 Jat Boy (DOB 24.11.94)26/5'11", B.Tech. in Computer Science, two year study in Canada. Job in Canada with PR. Father and mother in Govt. job at Panchkula. Avoid Gotras: Siwach, Malik, Bazad. Cont.: 9463188807.
- SM4 Jat Boy (DOB 28.10.91)29/5'10", B.Tech. from PEC Chandigarh. Working as Software Engineer in Banglore with package Rs. 13 lakh PA. Family settled in Zirakpur. Avoid Gotras: Kajla, Gawaria, Siwach, Khiyalia. Cont.: 9041149778
- SM4 Jat Boy (DOB 20.10.90)30/5'8", B. Tech.. Employed in IT company. Avoid Gotras: Malik, Khatkar. Cont.: 9463491567
- SM4 Jat Boy 33/6'2"Advocate, Practicing in Delhi. Father retired as Additional Secretary from Govt. of India. Mother retired school lecturer from Haryana Govt. Elder brother working in India Overseas Bank. Preferred girl in service.Avoid Gotras: Ahlawat, Malik,Sangwan. Cont.: 9023187793
- SM4 Jat Boy (DOB 20.04.91) 29/5'8"B.Tech.Computer Science.Working in Sparrow GG Solutions OPC ltd. With Rs. 6 lakh package PA. Avoid Gotras: Kadyan, Ahlawat, Dagar.Cont.: 9876855880
- SM4 Jat Boy (DOB 04.09.87) 33/5'10"B.Tech.ECE.Working as Junior Data Scientist in US based Research Lab at Noida. Father retired Headmaster from Delhi Govt. Avoid Gotras: Antil, Gehlot, Shokeen.Cont.: 9312063389
- SM4 Jat Boy (DOB 20.03.88) 32/5'11"Graduation in Photography.Only son.Own house in Urban Estate Panchkula. Father retired from gazetted post in Haryana Govt. Avoid Gotras: Panghal, Dalal, Sangwan.Cont.: 9646404899
- SM4 Jat Boy (DOB March 92) 28/5'9" B.S.c (Computer Science) from Punjab University. Pursuing MCA. Employed in Kurukshetra University Kurukshetra as Clerk on regular basis. Father in private job. Mother housewife. Sister married and employed in Punjab Government. Family settled in Mohali. Preferred match in Government job. Avoid Gotras: Jadge, Budhrain. Cont.: 9056787532.
- SM4 Jat Boy26/6'1"Polytechnic Electric Diploma.Working in MNC with package of Rs. 4 lakh PA. Mother retired teacher. Brother, sister well settled. Preferred tall girl in service.Avoid Gotras: Mor, Malik, Budhwar Cont.: 8295865543
- SM4 Jat Boy(DOB 26.05.94) 26/6'4"B.Tech.Mechanical Degree Auto Cat.Settled in Canada (Toronto). Father in Haryana Govt. Mother school teacher in Haryana Govt. Avoid Gotras: Sayan, Punia Cont.: 9416877531, 9417303417
- SM4 Divorcee Jat Boy (DOB11.05.81) 39/5'11"MBA (IT). Working in HCL Noida as Network Consultant. Preferred Tri-city/NCR match. Avoid Gotras: Deswal, Dahiya. Cont.: 9466629799
- SM4 Jat Boy 28/5'10" MBA (HR).Working in Maruti as Assistant Manager at Gurgaon. Father and mother both retired as Class-I Officers from Haryana Govt. Sister married and is class-I officer. Family settled in Panchkula. Avoid Gotras:Jatrana, Tewetia, Dagar. Cont.: 9988442438 (Whatsap) E.mail: tstewtia@gmail.com
- SM4 Jat Boy(DOB 10.03.90) 30/5'11"B.Sc (HM).Avoid Gotras: Sangwan, Punia, Sheoran. Cont.: 9888476688
- SM4 Jat Boy(DOB 01.01.88) 33/5'9" B. Tech. (Mechanical). Working in Central Govt. Chandigarh as Assistant Audit Officer in CAG Haryana cadre and also selected as S.I. in Delhi Police. Father retired govt. employee. Avoid Gotras: Sheoran, Sangwan, Punia. Cont.: 9217884178
- SM4 Jat Boy(DOB17.12.95) 25/6'1" Employed as Nursing officer in ESIC Hospital, Govt. of India in U.P. with salary of Rs. 82000/- PM. Preferred BDS, BAMS or employed match. Avoid Gotras: Bhanwala, Mann, Khatkar. Cont.: 9417579207
- SM4 Jat Boy (DOB 27.04.89)31/5'10" B.Tech.in Bio-Medical Engineering. Working in a reputed Master's Medical Company with package of Rs. 16.5 lacs PA. Father businessman.Mother housewife. Avoid Gotras: Jatyan, Duhan, Dagar. Cont.: 9818724242
- SM4 Divorced Jat Boy (DOB 13.09.86)34/5'9" B. Tech. Electrical. Working in Nipper Centre on contract basis. Avoid Gotras: Gill, Rathi, Goyat Cont.: 9417216868

दानवीर नांदल द्वारा यात्री निवास कटरा के लिये विशेष आर्थिक योगदान

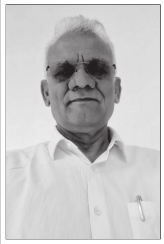

श्री सुखबीर सिंह नांदल सुपुत्र श्री ज्ञानी राम निवासी मकान नं. 426–427, नेमी सागर कालोनी, वैशाली नगर, जयपुर ने अत्यन्त श्रद्धा एवं विन्रमता पूर्वक 5,01,000 रुपये की राशि चौ० छोटूराम सेवा सदन यात्री निवास कटरा–जम्मू में कक्ष के निर्माण हेतू जाट सभा चण्डीगढ़ को सहर्ष और आदपूर्वक दान स्वरूप प्रदान की है।

जाट सभा चण्डीगढ़, पंचकूला एवं चौ० छोटूराम सेवा सदन कटरा–जम्मू के समस्त सदस्यगण इस पवित्र कार्य के लिये सार्वजनिकहित में दिये गये अनुदान के लिए श्री सुखबीर सिंह नांदल का तहदिल से अभिनन्दन व आभाग व्यक्त करते है और उनके व समस्त परिवार के सुखद स्वास्थ्य एवं मंगलमय भविष्य के लिये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते है।

प्रधान, जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला
चेयरमैन, चौ० छोटूराम सेवा सदन, कटरा–जम्मू

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान-नोमैई कटरा जम्मु में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू-स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मु) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। बिल्ड़िग के मजबूत ढ़ांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्ड़िंग के नक्शे/ड्राईंग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये है। इसके अलावा जम्मु प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें - छोटे बस स्टैड़, टू-व्हीलर सैल्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। यात्री निवास स्थल पर ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) कटरा द्वारा सरकारी खर्चे से दो महिला एवं पुरूष स्नानघर व शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और पानी के कनैक्शन के लिये भी सरकारी कोष से फंड मंजूर हो गया है और शीघ्र ही पानी की आपूर्ति का कनैक्शन चालू हो जायेगा।

जाट सभा द्वारा यात्री निवास भवन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का प्रयास था लेकिन कोविड़-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका और इस महामारी का जाट सभा की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला यात्री निवास भवन का निर्माण करने पर वचनबद्ध है और वर्ष 2021 में निर्माण शरू कर दिया जायेगा।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मु काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा0 जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा0 एम एस मलिक, भा0पु0से0 (सेवा निवृत) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होगें। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रैंस हाल, डिस्पैंसरी, मैडीकल स्टोर, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफ्त ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं। यात्री निवास के निर्माण के लिये श्री राम कंवर साहु सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह, गांव बीबपुर जिला जीन्द (हरियाणा), वर्तमान निवासी मकान नं0 110 सुभाष नगर, रोहतक द्वारा 5,11,111/- तथा श्री सुखबीर सिंह नांदल, निवासी मकान नं. 426-427, नेमी सागर कालोनी, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा 5,01,000 रुपये की राशि जाट सभा, चण्डीगढ को दान स्वरूप प्रदान की गई है।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संम्भव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मु काश्मीर के भाई-बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटु राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो0नं0 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो0नं0 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो0नं0 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फत सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)

सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान

साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक

प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798

वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़

फोन : 0172–2654932 2641127

Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला

फोन : 0172–2590870, Email: jatbhawan6pkl@gmail.com

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोसियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2–बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27–ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।